चिंतन

वो दिन दूर नहीं जब पाक का एक और बंटवारा होगा

बहुत पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसमें गिरता है। यही हाल पड़ोसी पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तानी हुकूमतन हरसंभव नापाक हरकत करते रहे कि किसी भी तरह से भारत को आतंकवाद की आग में झोंका जाए और वहां दहशत का माहौल बनाकर विश्व बिरादरी में भारत को बदनाम किया जाए, लेकिन हो गया है इसके बिल्कुल उलट। पाकिस्तानी सियासतदानों ने जिस आतंकवाद का भारत में दहशत फैलाने के लिए पोषण किया, उसे दूध पिलाया, आज वो उसे ही दहला रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन निकलता हो जब पाकिस्तान में बम धमाका न हो। हर रोज आतंकी वारदातें सामने आ रही हैं। मासूम नागरिक इसके शिकार हो रहे हैं। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान को दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देशभर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90 फीसदी इसी इलाके में हुई हैं। तहरीक-ए-तालिबान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया है। 2024 में इस ग्रुप ने 482 हमले किए, जिसकी वजह से 558 मौतें हुई थीं, जो 2023 के मुकाबले 91 प्रतिशत ज्यादा हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में हालात क्या हो गए हैं। मंगलवार को तो इसके दो कदम आगे बढ़कर बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए हिंसक आंदोलन कर रहे बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक पैसेंजर ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर पहरो कुनरी और गदलार के बीच भारी गोलीबारी की खबरें हैं, जिसमें 6 पाक सैनिकों की मौत हो गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने एक बियान में कहा कि हमारे लड़ाकों ने माशकाफ, धादर और बोलान में इस ऑपरेशन को प्लान किया है। रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस को रुकना पड़ा। इसके बाद हमारे लड़ाकों ने इस ट्रेन पर कब्जा कर लिया और यात्रियों को बंधक बना लिया, जिसमें 500 यात्री सवार थे। हमने सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कर्मियों को बंधक बनाया है। अगर हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। इस कत्ल-ए-आम की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। असल में बलूच का आंदोलन नया नहीं है। यह आजादी के बाद से ही सुलगता रहा है। भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने से चार दिन पहले बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था और 1947 में पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। इससे भी अधिक विडंबना यह थी कि बलूचिस्तान के शासक खान के मामले की पैरवी करने वाले वकील मुहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन बलूचिस्तान केवल 227 दिनों तक ही स्वतंत्र राष्ट्र रह सका। बाद में उसे पाकिस्तान में मिला दिया गया। इसी को लेकर बलूची नाराज हैं और लगातार अलग देश की मांग करते रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44 फीसदी हिस्सा है। यह प्राकृतिक संसाधनों तेल, सोना, तांबा और अन्य खदानों से समृद्ध है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का बांग्लादेश के बाद एक और बंटवारा हो जाएगा।

विमर्श
प्रो. महेश चंद गुप्ता

सनातन संस्कृति में पर्यावरण समस्या का हल

> विदेशों में बसा हिंदू समुदाय भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। इस बात को अब विदेशों में भी स्वीकार कर इससे प्रेरणा ली जाने लगी है। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ फेथ इन लाइफ (आईआईएफएल) की ओर से हाल में किए गए एक अध्ययन में यह निष्कर्ष सामने आया है। अध्ययन की रिपोर्ट में उल्लेख है कि पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर ब्रिटेन में हिंदू समुदाय बाकी समुदायों की तुलना में सबसे ज्यादा सक्रिय है। अधिकांश हिंदू पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। कण-कण में भगवान के होने का विश्वास उनका प्रेरणास्रोत है। प्रकृति की रक्षा करना केवल हमारा धर्म नहीं बल्कि हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है।

भारतीय सनातन संस्कृति और पर्यावरण के बीच युगों पुराना नाता है। एक सनातन संस्कृति ही है, जिसमें प्रकृति को केवल अस्तित्व का आधार ही नहीं बल्कि पूजनीय माना गया है। आधुनिक विज्ञान में जिस पर्यावरणीय संतुलन की वकालत की जाती है, उस संतुलन को सनातन परंपराओं में सदियों से साधा जा रहा है। सनातन संस्कृति में प्रत्येक प्राकृतिक तत्व को दिव्य माना गया है। हमारे लिए सूर्य, जल, वायु और वनस्पति सब देवतुल्य हैं। जरूरत के समय पेड़ों को काटने से पहले उनकी अनुमति मांगने और तुलसी पत्र तोड़ते समय विनम्र भाव से क्षमा मांगने की विनम्रता केवल हमारी संस्कृति में ही है।

हम सूर्यास्त के बाद फूल-पत्तियां इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि तब वे विश्राम की अवस्था में होते हैं। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में बसा हिंदू समुदाय भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। इस बात को अब विदेशों में भी स्वीकार कर इससे प्रेरणा ली जाने लगी है। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ फेथ इन लाइफ (आईआईएफएल) की ओर से हाल में किए गए एक अध्ययन में यह निष्कर्ष सामने आया है। अध्ययन की रिपोर्ट में उल्लेख है कि पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर ब्रिटेन में हिंदू समुदाय बाकी समुदायों की तुलना में सबसे ज्यादा सक्रिय है। अधिकांश हिंदू पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। कण-कण में भगवान के होने का विश्वास उनका प्रेरणास्रोत है। 64 फीसदी हिंदू 'रीवाइल्डिंग' यानी इको सिस्टम को नई जिंदगी देने में शामिल हैं। 78 फीसदी हिंदू अपनी आदतों में इसलिए बदलाव लाते हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान कम हो। 44 प्रतिशत हिंदू पर्यावरणीय संगठनों से जुड़े हैं। अध्ययन में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदायों के पर्यावरण संबंधी नजरिये और गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ब्रिटेन के 82 फीसदी ईसाई धर्म को पर्यावरण सुरक्षा से जोड़ते हैं पर उनके सुरक्षा संबंधी काम सबसे कम हैं। अगर हिंदू पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय हैं तो इसका मुख्य कारण यह है कि हिंदू धर्म में 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना निहित है जो संपूर्ण सृष्टि को एक परिवार के रूप में देखने की शिक्षा देती है। यही भाव हममें प्रकृति के प्रति एकात्मता का भाव विकसित करता है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है, तब सनातन संस्कृति की यह सोच और व्यवहार मानवता के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। यह अध्ययन पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन के खतरों के दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन से न सिर्फ सनातन संस्कृति और पर्यावरण के संबंधों का पता चलता है, वहीं यह बात भी साबित होती है कि दशकों पहले कामकाज के सिलसिले में विदेशों में बस गए हिंदू आज भी अपनी संस्कृति को आत्मसात किए हुए हैं। हिंदू सनातन धर्म में पर्यावरण केवल आध्यात्मिकता या पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के प्रति एक गहरी जागरूकता और सम्मान की भावना से ओत-प्रोत है। हमारी संस्कृति में प्रकृति और जीव-जंतुओं को पूजनीय मानते हुए उनके संरक्षण पर जोर दिया गया है। इससे हिंदू धर्म में पर्यावरण संरक्षण केवल नैतिक दायित्व नहीं है बल्कि धार्मिक आस्था और दैनिक जीवन का अभिन्न अंग भी है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि संपूर्ण सृष्टि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचतत्वों से बनी है। इन पंचतत्वों को संतुलित रखना जीवन का मूल

उद्देश्य है। इसी कारण पर्यावरण की शुद्धता और संतुलन बनाए रखना हिंदू दर्शन का प्रमुख भाग है। सनातन संस्कृति में पंच-पग पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय किए गए हैं। नदियों को देवी मानकर पूजने के पीछे गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा आदि तमाम नदियों की पवित्रता को बनाए रखने की मंशा ही तो है।

हवन और यज्ञ में प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का उपयोग करने के पीछे पर्यावरण को शुद्ध करने की भावना निहित है। हमारे पुरखों ने योग और प्राणायाम के जरिए शुद्ध वायु का महत्व कितने वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। पेड़ों और वनस्पतियों को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा के पीछे उनके संरक्षण की भावना ही तो है। सदियों पहले जिस तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर हर घर में लगाने की परंपरा शुरू की, उसके औषधीय गुणों को आज वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। हमारे यहां प्राचीन काल में ही ऋषि-मुनि आश्रमों में वन लगाने को प्राथमिकता दी गई और आज भी मंदिरों और आश्रमों में पौधरोपण को पवित्र कार्य के रूप में करके उसका अनुसरण किया जा रहा है। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण हमारी शिक्षा पद्धति का प्राचीन काल से ही भाग रहा है। हमारे ऋषि-मुनि पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए हवन-यज्ञ करते थे। इससे वातावरण को साफ एवं समय पर वर्षा में मदद मिलती थी। मौजूदा समय में तो प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि नदियों का जल कम एवं प्रदूषित हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और विश्व के कई तटीय शहरों के डूब जाने का अंदेशा है।

प्राचीन गुरुकुलों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जाता था तो मौजूदा दौर में भी कॉलेजों-विश्वविद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण पर शोध एवं अध्ययन, अधिकाधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण अनुकूलता के लिए स्वच्छ वातावरण को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारी मान्यता है कि शुद्ध एवं साफ वातावरण में लक्ष्मी का वास होता है और इससे समृद्धि आती है, हमारे इस विचार को विदेशों में अपनाया गया है। निश्चित देशों में विश्वविद्यालयों के लंबे-चौड़े, खुले परिसर एवं वहां सघन हरियाली इसका प्रमाण है। सनातन संस्कृति में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जहां गाय को माता का दर्जा दिया गया है, वहीं नाग पंचमी पर सांपों की पूजा कर उनके महत्व को भी स्वीकारा गया है। गंगा दशहरा और कार्तिक स्नान जैसे त्योहारों के माध्यम से जल शुद्धता बनाए रखने का संदेश दिया गया है। अद्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ में नदियों की सफाई और उनकी महत्ता पर बल दिया गया है। आज समूची दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन की समस्याओं से जूझ रही है। इन समस्याओं का समाधान भारतीय सनातन संस्कृति में खोजा जा सकता है। हमारी महान परंपराएं समूची दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन सकती हैं। हिंदू धर्म में पुराने कपड़ों और सामान का पुनः उपयोग करने की परंपरा रीसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन का प्राचीन रूप नहीं तो क्या है। हमारे यहां शाकाहार को बढ़ावा इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि शाकाहार को बढ़ावा देने से कार्बन उत्सर्जन कम होता है और पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है। हिंदू सनातन धर्म और पर्यावरण संरक्षण की भावना परस्पर गहराई से जुड़े हुए हैं। यह जुड़ाव केवल धार्मिक नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है जो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन, सम्मान और संरक्षण को प्राथमिकता देती है। अगर आज पूरी दुनिया इन सिद्धांतों को अपना ले तो न सिर्फ पर्यावरण संकट को कम किया जा सकता है बल्कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से भी निपटा जा सकता है। प्रकृति की रक्षा करना केवल हमारा धर्म नहीं बल्कि हमारा नैतिक उत्तरदायित्व भी है।

(लेखक प्रख्यात शिक्षाविद्, वक्ता व विचारक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

नो स्मोकिंग डे

योगेश कुमार गोयल

धूम्रपान मुक्त जीवन ही है स्वस्थ भविष्य की गारंटी

प्रतिवर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को 'धूम्रपान निषेध दिवस' मनाया जाता है, जो इस वर्ष 12 मार्च को मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य निकोटीन के आदी लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए मदद पाने को प्रोत्साहित करना है। यह समाज पर धूम्रपान के दुष्परिणामों को उजागर करने और जीवन के स्वस्थ तरीकों तथा धूम्रपान मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने का दिन है। पहली बार धूम्रपान निषेध दिवस 1984 में आयरलैंड गणराज्य में मनाया गया था। तब यह मार्च महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता था लेकिन समय के साथ यह मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाने लगा। उसके बाद से यूके सहित कई देशों में यह एक वार्षिक कार्यक्रम की भांति मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह दिवस एक खास विषय के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 'इस नो स्मोकिंग डे पर अपनी जिंदगी वापस लें' विषय के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय हमें यह याद दिलाता है कि धूम्रपान छोड़कर हम न केवल अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय भी बिता सकते हैं। धूम्रपान छोड़ने से हृदय रोग, कैंसर और सांस की बीमारियों का खतरा कम होता है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है क्योंकि धूम्रपान पर खर्च होने वाले पैसे की बचत की जा सकती है। कई अध्ययनों में यह तथ्य सामने आ चुका है कि सिगरेट तथा अन्य धूम्रपान उत्पादों में मौजूद रसायन प्रतिवर्ष लाखों लोगों की जान ले लेते हैं। दरअसल सिगरेट के धुएं में ऐसे रसायन होते हैं, जो धूम्रपान के दौरान और बाद में शरीर पर घातक प्रभाव डालते हैं। तंबाकू के सेवन से दुनियाभर में हर साल 80 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। निकोटीन विकासशील मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। व्यस्कों के मुकाबले बच्चों के बहुत जल्दी आदी हो जाने की भी संभावना है। धूम्रपान करने वाले बच्चों में निकोटीन अवसाद और चिंता से भी जुड़ा है। सार्वजनिक स्थलों के अलावा बंद कमरे में धूम्रपान करना तो धूम्रपान न करने वालों के लिए भी बेहद खतरनाक सिद्ध होता है, जिसके सबसे बड़े शिकार प्रायः घरों में बच्चे ही होते हैं।

चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि जिन बच्चों के माता-पिता बीड़ी-सिगरेट के आदी होते हैं, उन बच्चों में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसी सांस, गले और छाती की बीमारियां होना एक आम बात है। बच्चों में धूम्रपान के संपर्क में आने से श्वसन संक्रमण, कान में संक्रमण और अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। जहां तक तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा की बात है तो यह इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बच्चों का मन-मस्तिष्क बहुत कोमल होता है और तंबाकू उद्योग बच्चों को लक्षित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। ऐसे ही तरीकों में तंबाकू उद्योग आकर्षक विज्ञापनों और मार्केटिंग अभियानों का सहारा लेता है, जिनके जरिये बच्चों को तंबाकू उत्पादों को आकर्षक और वांछनीय लगने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिये भी तंबाकू कंपनियां बच्चों के साथ जुड़ने और उन्हें तंबाकू उत्पादों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करती हैं। धूम्रपान करने से बच्चों को अनेक प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य संवर्धन विभाग के निदेशक डा. रुडिगर क्रेच कहते हैं कि वे इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि तंबाकू उद्योग अनगिनत जिंदगियों की क़ीमत पर मुनाफ़ा कमाने के लिए इस हद तक जाएगा। उनके मुताबिक जैसे ही किसी देश की सरकार को लगता है कि उसने तंबाकू के खिलाफ लड़ाई जीत ली है, तंबाकू उद्योग स्वास्थ्य नीतियों में हेरफेर करने और अपने घातक उत्पादों को बेचने के अवसर को अपनी पकड़ में ले लेता है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि दुनियाभर में तंबाकू उद्योग के बढ़ते हस्तक्षेप से स्वास्थ्य नीति को बचाने के प्रयास लड़खड़ा गए हैं, इसीलिए उसने ऐसे में विभिन्न देशों से कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया है। चूंकि धूम्रपान करने से बच्चों में इसकी लत लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो उनके जीवन को कई प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, इसीलिए तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किया जाना समय की बहुत बड़ी मांग है। इसके लिए जरूरी यह भी है कि बच्चों तथा उनके माता-पिता को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप और तंबाकू उत्पादों के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं और तंबाकू उत्पादों के उपयोग से संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जीवन का मार्गदर्शन करती है अंतःकरण की आवाज

संकलित
दर्शन

हमारे अंतःकरण की आवाज हमारी मुख्य मार्गदर्शक होती है। यही हमें सही और गलत में अंतर का आभास कराती है। मनोविज्ञान के अनुसार, जब किसी मनुष्य का कोई कार्य, विचार और अभिव्यक्ति नैतिक मूल्यों के विपरीत परिणाम देती है तो अंतर्मन की आवाज उस व्यक्ति में ग्लानि और पश्चाताप की भावना को जन्म देती है, लेकिन जब हमारे कार्य नैतिक मूल्यों के अनुरूप परिणाम देते हैं तो इससे मन भीतर से प्रसन्न होता है। आज के इस कोलाहल भरे समय में हम प्रायः अपने अंतःकरण की आवाज को सुन नहीं पाते या उसे सुनकर उस पर अपेक्षित मनन नहीं करते। यही कारण है कि हम अपने जीवन में भटकाव महसूस करते हैं। महात्मा गांधी तो अंतःकरण की आवाज को ही सर्वोच्च मानते थे। उनके कई निर्णयों का आधार ही अंतःकरण की आवाज थी। इसी कारण गांधीजी सत्य के साथ खड़े रहे। इसीलिए उनके द्वारा किए गए अधिकांश प्रयोग सफल रहे। जीवन में सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्न रहने का सरल सा तरीका यही है कि हम अपने अंतःकरण की आवाज सुनें, क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली आवाज प्रत्येक परिस्थिति में सही होती है। हम जब कभी भी कुछ गलती या बुरा आचरण कर रहे होते हैं, तब हम अपनी भूल को जानते हैं। हमें कुछ अटपटा सा लगता है। भीतर से आवाज आती है कि यह कार्य उचित नहीं है। यही हमारे अंतःकरण की आवाज होती है। यही आवाज हमें कुछ गलत करने से रोकती है। जब हम अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना करते हैं तो अंततोगत्वा से हमारा संपर्क कमजोर हो जाता है।

अपने बल पर न करे घमंड न दूसरों को कमजोर समझे

संकलित
प्रेरणा

महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने-सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र-शस्त्रों से लैस रहे थे। जब-जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब-जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्रीकृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं, तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण ये रथ पीछे खिसक रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। यदि ये न होता तो पता नहीं तुम्हारे रथ की क्या स्थिति होती। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का अहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सीख दी कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। यथा स्थिति का अच्छा से अवलोकन करे।

अंतर्मन

आज की पाती

होली का त्योहार सामूहिक उमंग और उत्साह का प्रतीक

त्योहार और पर्वों की संस्कृति वन देश है भारत। इसमें हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार मानव-समाज की उमंगों एवं आशाओं के प्रतीक हैं। मनुष्य सहज ही आशावादी होता है, आशा ही उसे प्रसन्न और क्रियाशील रखती है। इसलिए आशाओं को जीवित और प्रखर रखने के लिए वह पर्व, त्योहार आदि उत्सव मनाता रहता है। त्योहारों में मानव जाति को संस्कार और शिक्षा देने की एक अन्तस्धारा छिपी रहती है। जैसे गंगा-यमुना के प्रवाह के भीतर सरस्वती का प्रवाह छिपा है। वैसे ही हमारे देश में हर त्योहार व पर्व के भीतर एक आदर्श समाज की कल्पना और भावना, मानव जाति के पारस्परिक प्रेम, समानता, हर्ष-उल्लास का संस्कार और आदर्शों की कल्पना इन पर्वों के पीछे छिपी है। – कांतिलाल मांडोत, सूरत

ट्रेंड

मॉरीशस में स्वागत

मॉरीशस ने अविस्मरणीय स्वागत से बहुत अभिभूत हूं। यहां वर्षों तक सफलता के भारतीयता प्रिय तरह रची-बसी है, उसकी पूरी झलक जीत-आई ने देखने को मिली। हमारी मोकशूरी भाषा मॉरीशस में मिश्र तरह से घल-घुल गई है, वह हर दिलों को जोरदार्यित करने वाली है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

अस्पताल का लोकार्पण

उत्तम विश्वस्त सुविधाओं तथा हर नागरिक वर्ग सुलभ और सुलभ पहुंच की सुनिश्चितता हमारी सीधी प्राथमिकता है। आज झांसी में 200 बेड के अस्पताल का लोकार्पण किया। 'स्वस्थ उत्तर प्रदेश' की संकल्पना की सिद्धि में नया उत्तर प्रदेश सतत गतिशील है।
-योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

जनप्रतिनिधि का कर्तव्य

जन भावनाओं को सुनना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का काम भी करता है। दिल्लीवालियों की हर संभव का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है।
-रेखा गुप्ता, सीएम, दिल्ली

सभी धर्मों का सम्मान

इस साल सलाम घर रहे हैं और होली घर में त्योहार आ रहा है। इसलिये आज मैं कोई भी सलामीति करना ठीक नहीं। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान-सम्मान का बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी।
-मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

करंट अफेयर

अफगानिस्तान की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं: भारत

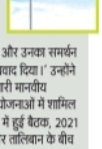

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि उसने तालिबान शासन के साथ द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है और लोगों से लोगों के 'विशेष' संबंध देश के भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने सोमवार को अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएमए) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बैठक में कहा कि इस साल की शुरुआत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी। हरीश ने परिषद में कहा, 'दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अफगान पक्ष ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ जुड़ने और उनका समर्थन करने के लिए भारतीय नेतृत्व की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया।' उन्होंने कहा, 'यह निर्णय लिया गया कि भारत, अफगानिस्तान में जारी मानवीय सहायता कार्यक्रमों के अलावा निकट भविष्य में विकास परियोजनाओं में शामिल होने पर विचार करेगा।' मिस्री और मुत्ताकी के बीच जनवरी में हुई बैठक, 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से भारत और तालिबान के बीच अब तक का सबसे उच्च स्तरीय संपर्क था।

ऑफ बीट

बैठने के बजाय खड़े होकर काम करना फायदेमंद है?

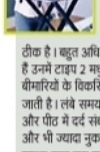

आधुनिक समय में हममें से अधिकतर लोग जागते हुए अपना अधिकांश समय बैठकर गुजारते हैं। हाल में एक अनुसंधान में लंबे समय तक बैठने के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों को रेखांकित किया गया है। कई कार्यस्थलों पर 'सिट-स्टैंड' डेस्क सिस्टम को अपनाया गया है, जिस पर आप लंबे समय तक बैठने के नुकसान से बचने के लिए डेस्क को बटन या लीवर दबाकर ऊंचा कर सकते हैं और खड़े होकर काम कर सकते हैं। लेकिन खड़ा होना बेहतर कैसे है? और क्या बहुत अधिक खड़े होने के भी नुकसान हैं? बहुत अधिक बैठने और खड़े होने के जोखिमों के बारे में अनुसंधान क्या कहता है, और क्या 'सिट-स्टैंड' डेस्क में निवेश करना ठीक है। बहुत अधिक बैठने के क्या नुकसान हैं? जो लोग बहुत अधिक बैठते हैं उनमें टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के विकसित होने और उनका जीवन कम होने की आशंका बढ़ जाती है। लंबे समय तक बैठे रहने से मांसपेशियों, हड्डियों में, खासकर गर्दन और पीठ में दर्द संबंधी शिकायत बढ़ जाती है। उन लोगों को अधिक बैठने से और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है जो बहुत कम व्यायाम करते हैं या एक मानक स्तर तक शारीरिक गतिविधियां नहीं करते।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 12 मार्च 2025

वादे हैं वादों का क्या

महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने हालिया विधानसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज करने के बाद जब सोमवार को अपना पहला बजट पेश किया तो उसके चुनावी वादों पर वित्तीय परेशानियों का बोझ साफ दिखा। लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने और किसानों का लोन माफ करने जैसे वादे पर सरकार पीछे हटती दिखी।

कर्ज का बोझ | पिछले साल लोकसभा चुनावों में महायुति को लगे झटके के बाद राज्य सरकार ने जो लोकलुभावन योजनाएं घोषित कीं, उनसे सरकारी खजाने पर करीब 96,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा। नतीजा यह हुआ कि इस बार के बजट में अनुमानित कर्ज अब तक की सभी सीमाएं पार करते हुए 9.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अनुमानित राजस्व घाटा यानी आमदनी और खर्च का अंतर भी बढ़कर 45,891 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

सरकार पीछे हटी

मतदाताओं में मायूसी | स्वाभाविक ही, राज्य सरकार के सामने उन वादों से पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन चुनाव से पहले महिला मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए तत्कालीन सरकार ने न केवल लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाई बल्कि कुछ किस्तों का भुगतान भी तत्काल कर दिया। ऐसे में मजबूरियां चाहे जो भी हों, उन मतदाताओं में जरूर मायूसी है जो यह मानकर बैठे थे कि चुनाव के बाद भी सरकार वादे पूरे करने में भी वैसी ही तत्परता दिखाएगी।

अन्य राज्यों का हाल | महाराष्ट्र सरकार इस मामले में अकेली नहीं है। दिल्ली में भी महिलाओं को तत्काल 2500 रुपये महीना देना शुरू कर देने का वादा सत्तारूढ़ BJP के लिए भारी पड़ रहा है। पंजाब की भगवंत मान सरकार तो महिलाओं को 1100 रुपये महीना देने का वादा भी इन्हीं कारणों से चुनाव के तीन साल बाद भी पूरा नहीं कर पाई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुफ्त पेशकश वाले वादों के ही चलते 1.16 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की सोच रही है, जिससे उसकी कुल देनदारी 7.64 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।

रेवड़ी कल्चर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ देश को सतर्क करते रहे हैं। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी भी इस पर अमल नहीं कर पाई। लेकिन चुनाव से पहले वादे और चुनाव के बाद वादा तोड़ने की यह स्थिति राजनीतिक बिरादरी को मतदाताओं की नजर में संदिग्ध बना रही है। देश के राजनीतिक दलों के लिए यह विचारणीय मुद्दा होना चाहिए।

कभी-कभी

दीवार पर बेलें

ललित वर्मा

पौधों में कुछ अलग होती है बेल। गमले में सिमट कर नहीं रहती। पेड़ भी नहीं बन पाती कभी। तना कमजोर होता है। उगते वक्त बहुत प्यार बरसता है इस पर। इर्द-गिर्द घेरा बनता है ईंटों का, ताकि आती-जाती भेड़ बकरी चट न कर दें इसके पत्ते। मगर एक दिन काट दी जाती है, भरी जवानी में। बोर हो जाते हैं इसे उगाने वाले। रोज एक ही बेल देखते-देखते। उन्हें लगने लगता है कि बहुत अतिक्रमण करने लगी है यह। कभी दूसरे की खिड़की पर चिपट रही है तो कभी उलझ रही है किसी बिजली के तार से। और एक दिन देर हुई दिखती है कोने में। एकदम फालतू।

कभी ध्यान से देखना इसे। बहुत मजबूत नहीं होता तना इसका। इसलिए पत्तों के साथ धागे से निकलते रहते हैं इसमें। गोल-गोल। स्प्रिंग से। आसपास जो भी दिखता है, उसी से लिपट जाते हैं। कसकर पकड़ लेते हैं। परवाह किए बगैर आत्मसम्मान की। बढ़ना होता है उसे, क्योंकि तना कमजोर होता है। बिना सहारे खड़ी नहीं हो सकती बेल। यूं ही धागे निकलते रहते हैं, लिपटते रहते हैं, और देखते ही देखते विशाल पत्तों का समूह हो जाती है। ढंक लेती है आसपास की बदसूरतियां। दीवार की सीलन, खुरदरी ईंटें, कबाड़ का सामान, एक दूसरे से उलझे तारों के गुच्छे। खूबसूरत दिखने लगता है सब। भर-भर कर आते हैं फूल। सेल्फियां खींची जाती हैं इसे बैकग्राउंड बनाकर। खाद पानी नहीं मांगती, तब यह कभी। बस फैलती रहती है। मगर चार साल-पांच साल से ज्यादा जीने नहीं देता कोई उसे। काटना मुश्किल भी तो नहीं होता न। तना कहां मजबूत होता है इसका। दो तीन वार किए और खत्म। बस फिर खींच कर तोड़ने होते हैं वे धागे, जिनके बूते चढ़ी थी कभी वह दीवार पर।

दीवार पर ही नहीं होती ऐसी बेलें। हमारे इर्द-गिर्द हर कहीं फैली होती हैं। पड़ोस में, दफ्तर में, रिश्तेदारी में, दोस्ती-यारी में। बचपन नहीं जीतीं अक्सर, क्योंकि जिम्मेदारियां उम्र से पहले कंधों पर सवार हो जाती हैं। कभी अपने इमोशंस की परवाह नहीं करतीं, मां-बाप, बहन-भाई के इमोशन कीमती होते हैं इनके लिए। फिर बीवी-बच्चों के। यूं ही दीवार से लटककर बिता देती हैं अपनी जिंदगी। आसपास की बदसूरती डंकते-डंकते एक दिन गिर पड़ती हैं अचानक। तना मजबूत कहां होता है इनका।

एकदा

कलाम की तैयारी

साल 2005 में पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ भारत के दौरे पर आए हुए थे। उन दिनों मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे। जब मीटिंग तय हो गई तो डॉ. कलाम के सचिव उनके पास गए और बोले, 'सर, कल आपकी जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ 30 मिनट की मीटिंग फिक्स हो गई है। मैं बस यह कहने आया हूं कि मुशर्रफ आपके समक्ष कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाएंगे, आप उसके लिए तैयार रहिएगा।' पीए की बात सुनकर डॉ. कलाम मुस्कुरा कर बोले, 'आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा।' अगले दिन निर्धारित समय पर मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग शुरू होते ही डॉ. कलाम ने जो बोलना प्रारंभ किया, तो मुशर्रफ को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। दरअसल कलाम, मुशर्रफ को प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज (PURA), यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की अवधारणा को ही समझाते रहे। उन्होंने मुशर्रफ को समझाया कि आने वाले 20 वर्षों में दोनों देश इसे कैसे हासिल कर सकते हैं और इससे दोनों देशों को क्या मिलेगा? इसी में निर्धारित समय खत्म हो गया। बैठक के बाद मुशर्रफ गहरी सांस लेकर बस एक ही वाक्य कह सके, 'धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय, भारत काफी भाग्यशाली है कि उनके पास आपके जैसा एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति है।'

Subrata Dhar

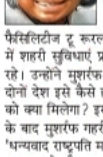

संकलन : रेनू सैनी

विदेश मंत्री ने लंदन दौरे पर कहा कि कश्मीर के पाक अधिकृत हिस्से की वापसी का है इंतज़ार

PoK पर जयशंकर के बयान का क्या है मतलब

अवधेश कुमार

पिछले दिनों ब्रिटेन और आयरलैंड के अपने छह दिवसीय दौरे के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में 'भारत का उदय और विश्व में उसकी भूमिका' विषय पर बोल रहे थे। एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम जिस दिन का इंतजार कर रहे हैं, वह है कश्मीर के उस हिस्से की वापसी जिसे पाकिस्तान ने चुराया है।

सवाल और विश्वास | जयशंकर के यह कहने के बाद लंबित भावनाओं के आलोक में सनसनी पैदा होनी चाहिए थी। इसके विपरीत जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रश्न किया कि आपको ऐसा करने से रोका किसने है? उमर की तरह के प्रश्न आपको सोशल मीडिया पर चारों ओर मिल जाएंगे। कारण इतना ही है कि किसी सरकार ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। 22 फरवरी, 1994 को संसद द्वारा सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर राज्य के अधिकृत क्षेत्र को खाली कराने का संकल्प केवल कागजों तक सीमित रह गया। ऐसे में आम लोग कैसे विश्वास करेंगे कि कोई सरकार PoK वापस लेगी?

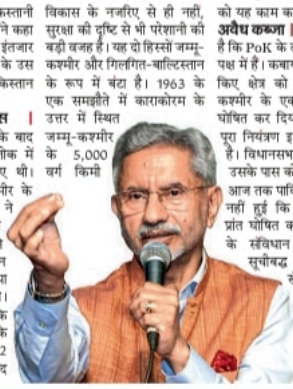

आज नहीं तो कल | पाक अधिकृत कश्मीर की वर्तमान स्थिति केवल क्षेत्र के आर्थिक विकास के नजरिए से ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी परेशानी की बड़ी वजह है। यह दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के रूप में बंटा है। 1963 के एक समझौते में काराकोरम के उत्तर में स्थित जम्मू-कश्मीर के 5,000 वर्ग किमी शक्सगाम क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। चीन पाक आर्थिक गलियारा वहीं से होकर ग्वादर बंदरगाह तक जाता है, जिसका भारत ने लगातार विरोध किया है। इसे भारत का अभिन्न अंग बनाए बिना हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकती है? इसलिए आज नहीं तो कल किसी सरकार को यह काम करना ही होगा।

अवैध कब्जा | यह मानना गलत है कि PoK के लोग पाकिस्तान के पक्ष में हैं। कबायलियों द्वारा कब्जा किए क्षेत्र को भले उस समय कश्मीर के एक वर्ग ने स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन इसका पूरा नियंत्रण इस्लामाबाद केंद्रित है। विधानसभा होने के बावजूद उसके पास कोई अधिकार नहीं। आज तक पाकिस्तान को हिम्मत नहीं हुई कि वह इसे अपना प्रांत घोषित कर दे। पाकिस्तान के संविधान में सिर्फ चार सूचीबद्ध प्रांत हैं- पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध। इसलिए यह गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हो चुका है।

AI Image

इंडिया जिंदाबाद | पाक नियंत्रित होने के बावजूद यहां लगातार इस्लामाबाद के विरुद्ध विद्रोह होते रहते हैं। कई तरह के खनिज और वन्य औषधीय संपदा होने के बावजूद यह क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। पाकिस्तान ने उसे आतंकवादियों के प्रशिक्षण, शरणस्थल और सीमा पार कराने के क्षेत्र में बदल दिया है। हाल के वर्षों में वहां कई आंदोलन हुए हैं जिनमें इंडिया जिंदाबाद के नारे लगे हैं। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बावजूद यहां इसका विरोध नहीं हुआ। 2015 के बाद से ही PoK के अनेक संगठन सामने आकर बोल रहे हैं कि जिस तरह भारत सरकार उसके एक हिस्से में विकास कर रही है, वह सब हमारे क्षेत्र में भी संभव होगा।

बलूचों की दोस्ती | PoK में अकेले गिलगित-बाल्टिस्तान 72,871 वर्ग किमी में फैला है। बाल्टिस्तान में अधिकतर बलूच हैं, तो इसे बलूचिस्तान भी कहा जाता है। बलूचों के अंदर पाक के विरोध और उससे मुक्ति का सघन संघर्ष है। बलूच विद्रोही नेता लगातार भारत से स्वतंत्रता के लिए मदद मांगते हैं। कभी भारत की ओर से ऐसे वक्तव्य के विरोध में यूरोप, अमेरिका से भी आवाजें आती थीं। इस बार पाकिस्तान को छोड़कर एक भी स्वर विरोध में नहीं आया।

चल रही तैयारी | एक समय ऐसा माहौल था कि भारत ने सैन्य कार्रवाई की तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर देगा। इसी आशंका से यूरोप-अमेरिका भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते थे। सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई बमबारी के बाद यह मिथक समाप्त हो चुका है। ऐसे में बदले वातावरण और केंद्र की मौजूदा सरकार का ट्रैक रेकॉर्ड देखें तो समझ में आएगा कि PoK के लिए कोई न कोई तैयारी जरूर चल रही है।

(लेखक पत्रकार व विचारक हैं)

अंतरिक्ष से क्या ला रही हैं सुनीता विलियम्स

नौ महीने से इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथ गए ऐस्ट्रोनॉट विलमोर धरती पर लौटने की तैयारी में हैं। सभी को इनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है। जानते हैं इनकी वापसी, हासिल और ISS का हाल :

रिटर्न टिकट

इसी हफ्ते लॉन्च होगा स्पेसएक्स कैप्सूल।

इसमें होंगे सुनीता और विलमोर के रिप्लेसमेंट।

रिप्लेसमेंट्स

निक हेग, NASA

अलेक्जेंडर गोरबुनोव, रॉसकोमॉस

जून 2024 में सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर रवाना।

बोइंग की पहली मानवयुक्त यान टेस्टिंग।

फंसी वापसी

डॉकिंग से पहले फ्यूल टैंक लीक, थ्रस्टर रॉकेट फेल।

किसी तरह से हुई डॉकिंग, तब से दोनों हैं फंसे।

क्या किया

- कई प्रयोगों और मरम्मत में हिस्सा लिया।
- नेविगेशन सिस्टम बदले, टेलिस्कोप पुर्जों की मरम्मत।
- स्टेशन की बाहरी सतह से नमूने लिए।

वापसी की राजनीति

ट्रंप का दावा, उन्होंने मस्क से की बात।

मस्क ने दो हफ्ते में लाने का किया वादा।

ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडन पर डाला दोष।

बोले, आठ दिन के काम में 8 महीने लगा दिए।

हासिल

9 महीने तक सुनीता के शरीर पर असर का अध्ययन।

डेटा कई चिकित्सकीय अध्ययन में जोड़ा जाएगा।

सुनीता ने जनवरी 2025 में स्पेसवॉक के दौरान नमूने लिए।

स्टडी से बेहतर व्यायाम, आहार और दवाएं होंगी डिवेलप।

शोध से पता चलेगा कि सूक्ष्मजीव अंतरिक्ष में कैसे बचते हैं।

यह चंद्रमा और मंगल वेस के लिए अहम होगा।

धरती पर पांव

- 270 दिन बाद ग्रैविटी में आएंगी सुनीता।
- चलना भी भूलने की बात कही सुनीता ने।
- अंदर भी आ चुके हैं कई बदलाव।
- बैक्टीरिया और वायरस आने का खतरा।

शरीर पर क्या असर...

लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से हेल्थ माइक्रोबिएटी में ढल जाती है

चक्कर, चेहरे पर सूजन, संतुलन तंत्र गड़बड़।

कलम उठाना भी हो जाता है भारी।

हड्डियां कमजोर, फ्रैक्चर का खतरा।

मांसपेशियां कमजोर, पैरों-पीठ पर अधिक असर।

सुनीता रोज 2 घंटे व्यायाम करती थीं।

ट्रेडमिल, साइकल, भारोत्तोलन किया।

तब भी नॉर्मल होने में लगेंगे 6-8 हफ्ते।

अंतरिक्ष के धुरंधर

438 दिन वैलेरी पोल्याकोव (रूस)

379 दिन सर्गेई अवदीव (रूस)

370 दिन, सर्गेई प्रोकोपिएव, दिमित्री पेटेलिन (रूस)

365 दिन व्लादिमीर तीतोव और मूसा मनारोव (रूस)

पहली महिला

328 दिन क्रिस्टीना कोच (अमेरिका)

कंटेंट: राहुल पाण्डेय, ग्राफिक्स: अर्जुन सिंह

ISS का खात्मा

1998 में लॉन्च हुआ (2030 तक होना है खात्मा)

मस्क: 2030 से पहले हो खात्मा, जरूरत नहीं है इसकी।

सुनीता : स्टेशन पूरी तरह एक्टिव, शानदार तरीके से कर रहा काम।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

मन में स्पेस खाली होगा, तभी तो आएगा नया ज्ञान

सुरक्षित गोस्वामी

ज्ञान, प्रेम, आध्यात्मिक उन्नति सभी पाना चाहते हैं। इसकी क्षमता भी सभी में है। पर पाएंगे कैसे? जब हम खाली होंगे, तभी न कुछ अपने अंदर भर पाएंगे। जैसे एक मोबाइल फोन में नया डेटा डाउनलोड करने के लिए पर्याप्त स्टोरेज या स्पेस होना जरूरी है, वैसे ही हमें भी नया ज्ञान पाने के लिए अपने मन को अहंकार और नकारात्मक विचारों से खाली रखना होगा। लेकिन चुपके से हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और हमें पता भी नहीं चल पाता।

एक भिखारी को आपने एक रुपया दिया और शाम को वही भिखारी मिल गया। उसे देखकर याद किया कि उसे तो पहले ही दे चुके हैं। आपने केवल एक रुपया नहीं दिया, बल्कि देने का अहंकार भी पाल लिया। वास्तव में देने का सही अर्थ तभी होता है जब देने के बाद हमें याद भी न रहे कि हमने किसी को कुछ दिया है। यदि देने के बाद भी स्मरण बना रहे, तो यह निष्काम कर्म नहीं, बल्कि अपने अहंकार को पोषित करना है। वही हाल प्रेम का भी है।

संतों ने कहा है कि 'प्रेम गली अति सांकरी, तामें दो न समाए।' यानी प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, तभी हमारे भीतर दिव्यता प्रकट होती है। झुकने की प्रवृत्ति ही हमें सच्ची विनम्रता और ज्ञान की ओर ले जाती है। जैसे पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है। पानी कभी पहाड़ पर जमा नहीं होता, वह गड्ढे में ही जमा होता है। वैसे ही सच्चा ज्ञान और कृपा वहां जाते हैं, जहां अहंकार का अभाव हो। पर्वत कभी पानी से नहीं भरते, लेकिन समुद्र सबसे अधिक झुका होने के कारण सारा पानी अपने अंदर समाहित कर लेता है।

इसी प्रकार, जब हम झुकते हैं, तो हमें अधिक मिलता है, और जब हम अहंकार में उठते हैं, तो खाली हो जाते हैं। सच्चा ज्ञान और ईश्वरीय कृपा वहीं प्रवाहित होते हैं, जहां समर्पण और विनम्रता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हम शरीर से झुक भी जाएं, पर मन में अहंकार बना रहे, तो सच्ची श्रद्धा नहीं आ सकती। बड़ों के चरण स्पर्श करना तभी फलदायी होगा, जब यह सच्ची श्रद्धा और विनम्रता से किया जाए, न कि केवल दिखावे के लिए।

इसलिए खुद को समर्पित करना, खाली करना महत्वपूर्ण है। जब तक हम अंदर से खाली नहीं होंगे, तब तक नया ज्ञान और सच्ची अनुभूति हमारे भीतर नहीं आ सकती।

क्या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि संस्कृत है?

वृष्टि गुहा

यज्ञदेवम उर्फ भरत राव क्रिप्टोग्राफर हैं। वह उन गिने-चुने विशेषज्ञों में हैं, जिन्होंने सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने का दावा किया है। मिट्टी के बर्तनों पर अंकित सिंधु लिपि के चिह्न 4000 ईसा पूर्व के हैं।

भाषा की मदद | कई प्राचीन लिपियों को द्विभाषी या त्रिभाषी शिलालेखों के जरिये समझा गया है। Champollion इजिप्ट की प्राचीन चित्रलिपि hieroglyphics को इसलिए पढ़ पाए, क्योंकि एक पत्थर पर ग्रीक भाषा और इजिप्ट की चित्रलिपि में एक ही नाम लिखा था। इसी तरह, Henry Rawlinson को ईरान के जाग्रोस पर्वत पर जो शिलालेख मिला, उस पर तीन भाषाएं थीं - पुरानी फारसी, एलामाइट और सुमेरियन। उन्हें फारसी का ज्ञान था। अपने देश में भी ब्राह्मी लिपि को इसी तरह समझा गया। इंडो-बैक्ट्रियन राजा Agathocles के सिक्के पर एक तरफ उसका नाम ग्रीक में और दूसरी तरफ ब्राह्मी में लिखा था। हालांकि सिंधु घाटी में ऐसे शिलालेख अभी तक नहीं मिले हैं, जिन पर दो भाषाएं हों।

गुप्त कोड | यज्ञदेवम ने क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया। उन्होंने मॉडर्न इन्फॉर्मेशन थिअरी देने वाले Claude Shannon के 1945 के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान Shannon को यह पता लगाने का काम दिया गया था कि गुप्त कोड को कैसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाए। उन्होंने पाया कि अगर पर्याप्त कोडेड मेसेज पढ़ लिए जाएं, तो किसी भी कोड को तोड़ा जा सकता है।

पैटर्न की पहेली | पहले के ज्यादातर प्रयासों में सिंधु लिपि के छोटे अभिलेखों के चिह्नों को कुछ निश्चित अर्थ दिए गए। लेकिन जब वही चिह्न लंबे अभिलेखों में मिले, तो वे पहले दिए गए अर्थ से मेल नहीं खाए। इस वजह से कोई अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन पाया। यज्ञदेवम ने निष्कर्ष निकाला कि सिंधु लिपि agglutinative language नहीं हो सकती, जैसे कि द्रविड़, सुमेरियन, एलामाइट या हित्ती। वजह कि इनके और सिंधु लिपि के चिह्नों के पैटर्न में अंतर था। सिंधु लिपि में कुछ जगहों पर एक ही चिह्न को लगातार तीन बार दोहराया गया था। ऐसा प्राचीन वैदिक संस्कृत में देखने को मिलता है।

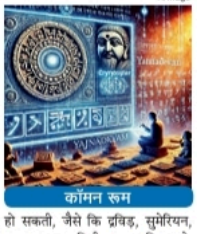

AI Image

कॉमन रूम

चिह्नों की पहचान | यज्ञदेवम ने सिंधु लिपि को संस्कृत भाषा में लिखी मानकर पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने सबसे ज्यादा बार आने वाले चिह्नों को पहचाना, फिर उसके साथ बार-बार दिखने वाले चिह्नों को देखा। इसी तरह उन्होंने सभी चिह्नों के अर्थ तय किए और जब इन्हें मिलाया तो एक मतलब निकल गया। इन अभिलेखों में देवताओं, हवन, घोड़ों और भोजन का जिक्र है। कुछ मेसेज में लिखने वाले ने लिखा है कि समुद्र ही उसका घर है। कुछ में सिंधु और ब्राह्मी लिपि साथ में लिखी गई थीं। इससे यज्ञदेवम ने निष्कर्ष निकाला कि ब्राह्मी लिपि, सिंधु लिपि से ही विकसित हुई।

इतिहास पर असर | आर्य आक्रमण सिद्धांत के अनुसार, 1500 ईसा पूर्व में आक्रमणकारियों के साथ संस्कृत भारत आई थी। लेकिन यज्ञदेवम के मुताबिक, संस्कृत 4000 ईसा पूर्व न केवल बोली जा रही थी, बल्कि इसे लिखा भी जा रहा था। आर्य थिअरी ने बताया कि उत्तर भारत के लोग बाहर से आए आर्यों के वंशज हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी दक्षिण भारत चले गए और द्रविड़ भाषाएं बोलने लगे। यज्ञदेवम ने इसे गलत करार दिया है।

(लेखिका स्कूल ऑफ इंटरनैशनल स्टडीज, JNU में असोसिएट प्रफेसर हैं)

हमने भाषा विशेषज्ञों के साथ मिलकर उन क्षेत्रों के लिए स्त्रीलिंग शब्द बनाए, जिनके लिए सिर्फ पुल्लिंग शब्द ही थे। लोगों से हम यह अनुरोध करते हैं कि वह दोनों लिंगों के शब्दों का इस्तेमाल करें, जिस तरह महोदय/महोदया का उपयोग करते हैं।

इस पहल के बारे में आप अपनी राय बताएं हमें nbtreader@timesofindia.com पर

आरएनआई नं. 11-2122-2 एसीपीएम: पुलिस। विविध लाइसेंस के बिना अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय पुष्टि: डीसीपीएल (एस.एसीपीएल) दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय डाक अनुमति डिवीजन के लिए पंजीकृत पत्रकार द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 में प्रकाशित एवं प्रकाशक **राहुल कुमार वर्मा** द्वारा, **टाइम्स हाउस पब्लिकेशन्स** और नवभारत टाइम्स, 7 बी, बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 में मुद्रित। प्रधान संपादक: **राजीव सचदेव**, संपादक (ई-पेपर): **राजीव सचदेव**। विस्तार पेज मुद्रक: 1 से 10, बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 से मुद्रित। संपादक (ई-पेपर): रिपोर्ट 1 से 10, संपादक: रिपोर्ट 1 से 10, संपादक: रिपोर्ट मार्केट। अनुमति नहीं है इस अंक में प्रकाशित लेखों/सामग्री के पुनर्मुद्रण के लिए इसे संपादक के पूर्व में अनुमति लेकर प्रकाशित करना चाहाएंगे।

दैनिक जागरण
आचरण व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है

व्यर्थ का शोर

मतदाता सूची में गड़बड़ी और मतदाता पहचान पत्रों के क्रमांक में दोहराव को लेकर संसद में हंगामा जारी है, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इन मुद्दों पर हंगामा करने के बजाय इस पर गंभीरता के साथ विचार-विमर्श होना चाहिए कि मतदाता सूचियों की कथित गड़बड़ी कैसे रोकी जाए, लेकिन सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि मतदाता सूचियों में कैसी गड़बड़ी होती है और क्या विपक्षी दलों की ओर से जैसी गड़बड़ी की शिकायत की जा रही है, वैसी वास्तव में हो भी रही है? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि कुछ विपक्षी दल यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में चुनाव आयोग जानबूझकर त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची बना रहा है, ताकि भाजपा और उसके सहयोगी दलों को चुनावी लाभ मिल सके। मतदाता सूची तैयार करने का काम चुनाव आयोग करता है और इसके लिए वह जिस सरकारी मशीनरी का सहारा लेता है, उस पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है। यदि विपक्ष यह कहना चाहता है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में भी सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग के दबाव में गलत मतदाता सूचियां तैयार करती है तो इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का सवाल उठाकर विपक्ष लोगों का ध्यान खींचने में इसलिए नाकाम है, क्योंकि एक तो वह कोई पुष्ट प्रमाण सामने नहीं रख पा रहा और दूसरे, वह साबित करने की अतिरेक कोशिश कर रहा कि चुनावों में धांधली होती है। वह चुनावों में धांधली का शोर मचाते हुए हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों का तो उल्लेख कर रहा है, लेकिन जम्मू-कश्मीर और झारखंड का जिक्र करने से बच रहा है। क्या वह यह कहना चाहता है कि जहां-जहां उसे पराजय मिलती है, वहीं-वहीं धांधली होती है?

समस्या केवल यह नहीं है कि विपक्षी दल चुनाव आयोग को बदनाम करने में लगे हुए हैं, बल्कि यह भी है कि वे अपने मनगढ़ंत आरोपों के सहारे चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा करने का काम कर रहे हैं। क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में संदेह के बीज बोना लोकतंत्र विरोधी आचरण ही है। यह किसी से छिपा नहीं कि विपक्षी दल जब-तब ईवीएम का विरोध करने के लिए आगे आ जाते हैं और यह जानते हुए भी मतपत्रों के जरिये चुनाव कराने की मांग करने लगते हैं कि उनसे कितने बड़े पैमाने पर धांधली होती थी। विपक्षी दल मतदाता पहचान पत्रों में एक जैसे नंबर का मामला भी इस तरह उठा रहे हैं जैसे इससे भी चुनावी धांधली होती हो। तथ्य यह है कि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि मतदाता पहचान पत्र की क्रमांक संख्या में दोहराव के बावजूद कोई अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकता है।

जीवन चुनना था बेटी

अभिभावक होना कितना संवेदनशील विषय है और पारदर्शी संवाद का महत्व क्या है, यह जिम्मी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक छात्रा की आत्महत्या जैसे दुःखद प्रकरण से फिर जगा है। पिता ने यही पाया कि अगले दिन परीक्षा है और बेटी आधी रात को फोन का प्रयोग कर रही है। फोन लेने पर उसने घर से भाग कर पुल से छलांग लगा दी। अगले दिन ब्यास के किनारे जो दृश्य बना, वह त्रासद था। बेटी के शव के पास खड़े पिता आघात भी झेल रहे हैं और सवालों की बौछार भी। हिमाचल प्रदेश में तीन बड़े शत्रु किशोरों और बच्चों निशाना बना रहे हैं। एक नशा, दूसरा मोबाइल फोन और तीसरा जंक फूड। एक पिता इस आशा में देहात से शहर तक बच्ची को लाया कि वह पढ़ लिख कर अभिनेता बने, किंतु ईश्वर की एक अमूल्य कृति केवल एक फोन की जिद के कारण आत्महंता बन गई। यह जहाँ से अलग होने का संकेत तो है ही, बच्चों के साथ सतत संवाद की कमी का परिचायक भी है। फोन वापस लेने का ध्यान परीक्षा की रात को आया, यह अच्छी बात है, किंतु फोन का लगातार प्रयोग आदत कैसे बन गया, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि नई पौध उस अतिरेक तक पहुंच रही है जहां अपने भले-बुरे का अंतर मिट गया है, जहां मोबाइल की लत जीवन पर भारी पड़ रही है। यह दायित्व परिवारों का ही है कि जीवन के साथ कुछ नई पौध को जीवन के मूल्य भी दिए जाएं।

हिमाचल प्रदेश में नशा, मोबाइल फोन और जंक फूड किशोरों और बच्चों को बना रहे निशाना

सामूहिक प्रयासों का परिणाम

तरुण गुप्त

क्रिकेट टीम खेल है, जिसमें व्यक्तिगत उत्कृष्टता गाहे-बगाहे तो सफलता दिला सकती है, मगर निरंतर सफलता के लिए एक मजबूत एवं संतुलित टीम अनिवार्य है

अवधेश राजपूत

यह एक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम खूबसूरत तस्वीरों को बार-बार देखना चाहते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यह स्वतंत्रता ले रहा हूं कि प्रसन्नता के उन पलों को पुनः जीवंत करने का प्रयास करूं। क्रिकेट एवं सिनेमा मनोरंजन के हमारे सबसे बड़े साधन रहे हैं। समय के साथ मनोरंजन के परिदृश्य पर तमाम माध्यमों के उभार के बावजूद किसी बड़ी क्रिकेट विजय की संभवतः आज भी कोई बराबरी नहीं। चैंपियंस ट्राफी विजय ने हमें फिर से हर्ष की अनुभूति कराई है। दर्शकों से हमारी क्रिकेट टीम मजबूत बनी हुई है। अतीत में भी कुछ बड़ी उपलब्धियां हमारे नाम रही हैं। हर सफलता की भांति इस विजय के साथ भी कुछ विशेष पहलू उभरे हैं।

भारत ने विश्व क्रिकेट को अद्वितीय प्रतिभाएं दी हैं। सुनील गावस्कर और कपिल देव से लेकर सचिन तेंदुलकर के उभार तक हमारे पास खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। जहां सर्वकालिक महान बल्लेबाज गावस्कर एवं श्रेष्ठ तेज गेंदबाजी आलराउंडर कपिल देव समकालीन थे, वहीं तेंदुलकर इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी क्रम के अग्रदूत रहे। उनके ठीक में भी हमारे लिए गौरव के कई क्षण आए, फिर भी उसमें कहीं न कहीं निरंतरता का अभाव रहा। इसका सबसे तार्किक कारण यही समझा जा सकता है कि क्रिकेट एक टीम खेल है, जिसमें व्यक्तिगत उत्कृष्टता गाहे-बगाहे तो सफलता दिला सकती है, लेकिन निरंतर सफलता के लिए एक मजबूत एवं संतुलित टीम अनिवार्य है।

चैंपियंस ट्राफी इस मामले में अलग दिखती है। यह उत्तर सामूहिक प्रयासों का परिणाम रही। हमने देखा कि पूरी स्पर्धा के दौरान अलग-अलग खिलाड़ियों ने आगे आकर मोर्चा संभाला और जीत में अपना योगदान दिया। आरंभ से ही टीम ने सही निर्णय लिए। परिस्थितियों को बेहतर तरीके से परखा और अपना सर्वश्रेष्ठ संयोजन मैदान पर उतारा। टीम प्रबंधन को इसका भी श्रेय जाता है कि उसने टेस्ट क्रिकेट में पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला और फिर आस्ट्रेलिया में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सफेद गेंद वाले प्रारूप में समयानुकूल ढलने का बढ़िया काम किया। टीम की जीत में वरिष्ठ दिग्गजों से लेकर युवा बल्लेबाजों ने उपयुक्त समय पर अपना योगदान दिया। हमारे बल्लेबाजी क्रम की गहराई और दबाव झेलने की क्षमता ने हमें अलग स्तर पर पहुंचाया। सीमित ओवर क्रिकेट में चार स्पिनरों को खिलाने के लिए बहुत साहस चाहिए। यह विचित्र लग सकता है कि हम शामी के रूप में मात्र एक विशुद्ध तेज गेंदबाज और विशेषज्ञ स्पिनर के रूप में केवल वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के साथ उतरे, जबकि शेष गेंदबाज असल में आलराउंडर थे, जिन्होंने स्थितियों की मांग के अनुरूप शानदार प्रदर्शन दिखाया। यह एक रणनीतिक गलती भी साबित हो सकती थी, जो अंततः मास्टरस्ट्रोक बन गया। इससे जहां हमारे बल्लेबाजी क्रम की गहराई मिली तो छठे गेंदबाज का विकल्प भी मिल गया।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान सफेद गेंद वाले प्रारूप में हमारी टीम अद्भुत निरंतरता के साथ प्रदर्शन करने में सफल रही है। पिछले तीन आइसीसी टूर्नामेंट-2023 विश्व कप, 2024 टी-20 विश्व कप और हाल में संपन्न चैंपियंस ट्राफी तक हमने 24 में 23 मैच जीते हैं। एकमात्र हार 2023 के विश्व कप फाइनल में आस्ट्रेलिया से मिली थी। जीत का यह औसत एक विलक्षण उपलब्धि है। पिछले वर्षों में यही एक अफसोस रहा कि प्रबल दावेदार होने के बावजूद हम कोई आइसीसी ट्राफी नहीं जीत पा रहे थे और लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बावजूद नाकआउट दौर में हारकर बाहर हो जा रहे थे। गत वर्ष टी-20 विश्व कप में मिली जीत ने इस क्रम को तोड़ने का काम किया, जिसे इस जीत ने और आगे बढ़ाया। आज हमारी स्थिति अन्य टीमों के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकती है। सीमित ओवर क्रिकेट में हमारी टीम सर्वश्रेष्ठ है। इसकी गहराई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हमारी दूसरे दर्जे की टीम भी तमाम देशों की मुख्य टीमों का सामना करने में सक्षम है।

वर्तमान में जश्न के साथ ही भविष्य पर दृष्टि भी आवश्यक है। हमारे दो सबसे बड़े दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। एकदिवसीय क्रिकेट में निःसंदेह वे इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में हैं और इस टूर्नामेंट ने यह भी दर्शाया कि इस प्रारूप में अगले कुछ वर्षों में उनकी महत्ता बनी रहेगी। इस प्रारूप से इतर टी-20 अंतरराष्ट्रीय से दोनों पहले ही संन्यास ले चुके हैं। जहां कोहली में अभी भी टेस्ट क्रिकेट शेष दिखती है, वहीं संभवतः सबसे लंबे प्रारूप में रोहित के भविष्य को लेकर विचार किया जाना चाहिए।

सफलता अपने साथ सीतोष लाती है तो वह आकांक्षे भी बनाती है। हमारे पास जहां एक और उत्साह एवं प्रतिभा की भरमार है, वहीं उतनी ही लोकप्रियता और संसाधनों को देखते हुए यह अवश्य खटकता है कि अभी तक हमने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी नहीं जीती है। अतीत की महान टीमों का खेल के हर प्रारूप में वर्चस्व रहा है। यह खिताब दो बार हमारे हाथ से फिसल चुका है और इस बार तो हम फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। उम्मीद है कि डब्ल्यूटीसी के अगले चक्र में हम सफल होंगे। आगे की राह देखें तो हमारे लक्ष्य एकदम स्पष्ट होने चाहिए-2026 का टी-20 विश्व कप, डब्ल्यूटीसी 2025-27 और 2027 वनडे विश्व कप।

क्या हमारे अन्य खेल संघ क्रिकेट प्रशासकों से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम 2028 ओलिंपिक में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आस कर सकते हैं? हम 2036 ओलिंपिक मेजबानी की दावेदारी कर रहे हैं तो उस दिशा में हमारे लिए एक प्रमुख खेल राष्ट्र के रूप में उभरना भी उपयुक्त होगा।

चैंपियंस ट्राफी चैंपियन बनने में कुछ अंतर्निहित उपलब्धियां भी प्राप्त हुई हैं। 1989 में प्रथम प्रधानमंत्री की जन्मशती पर हमने नेहरू कप आयोजित किया था। तब बोलकाता में अपने चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को टूर्नामेंट जीतता देख हमें बड़ी निराशा हुई थी। अब दुबई में हमारे खिलाड़ियों को विजेता बनने पर जो सफेद ब्लेजर मिला, उस पर मेजबान के रूप में पाकिस्तान का नाम था। खेल इतिहास खट्टी-मीठी यादों से भरा है। खेलप्रेमियों की एक पीढ़ी ने जिस प्रकार पाकिस्तान के प्रभुत्व को देखा है तो यकीनन उन्हें इससे बहुत आनंद मिला होगा।

response@jagran.com

औरंगजेब से त्रस्त आइएनडीआइए

राजीव सचान

तिपक्षी गठबंधन जब तक छद्म सेक्युलरिज्म से चिपका रहेगा, तब तक अबू आजमी जैसे नेता उसके समक्ष संकट खड़ा करते रहेंगे

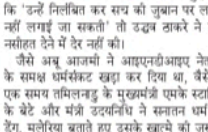

अबू आजमी का पुतला जलाता सिखों का समूह। एएनआइ

महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमामंडन करने वाले अपने बयान को वापस ले लिया, लेकिन वह राजनीतिक बहस और विवाद के केंद्र में बने हुए हैं। इसी बीच कुछ और लोगों को औरंगजेब दयालु दिख गया और उन्होंने भी उसकी प्रशंसा के पुल बांधने में संकोच नहीं किया। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि औरंगजेब एक कट्टर और क्रूर शासक था। आखिर जो अपने सगे भाई दारा शिकोह का सिर कलम करके उसका सिर तश्तरी में पिता शाहजहां को भेंट करने की हिमाकत करे, उससे निकृष्ट और कौन होगा? उसकी करतूतों का कच्चा-चिट्ठा खुद उसके दरबारी लेखक साकी मुस्तैद खान ने मआसिर-ए-आलमगिरी में लिखा है। वास्तव में इसी कारण करीब-करीब सभी इतिहासकार इस पर एकमत हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था और उसकी सनक भरी हरकतों की वजह से ही मुगल शासन का पतन हुआ। इसके बाद भी भारत और पाकिस्तान में उसका महिमामंडन करने वालों की कमी नहीं। पता नहीं क्यों, कुछ मुसलमानों को यह लगता है कि औरंगजेब चार लाख बुरा हो, लेकिन मुसलमान होने के नाते उसकी सराहना करना उनका मजहबी फर्ज है। कुछ लिबरल किस्म के बुद्धिजीवियों को भी यही लगता है कि वे जब तक औरंगजेब को महान और दयालु शासक नहीं कह देते, तब तक उनके लिए खुद को सेक्युलर साबित करना कठिन होगा। इस कारण वे भी औरंगजेब और ऐसे ही आक्रांताओं का गुणगान करना अपना सेक्युलर फर्ज समझते हैं।

यह तो गनीमत रही कि अबू आजमी औरंगजेब का महिमामंडन करने से पीछे हट गए, अन्यथा वह विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए के समक्ष बड़ा संकट खड़ा करने वाले थे। वैसे यह संकट अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों के लिए यह संभव नहीं कि वे औरंगजेब का महिमामंडन सहन कर सकें। इनमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के दोनों घटक ही नहीं, कांग्रेस भी है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अबू सपा प्रमुख अखिलेश ने औरंगजेब की सराहना पर अबू आजमी के महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि 'उन्हें निलंबित कर सच की जुबान पर लगाम नहीं लगाई जा सकती' तो उद्धव ठाकरे ने उन्हें नसीहत देने में देर नहीं की।

जैसे अबू आजमी ने आइएनडीआइए नेताओं के समक्ष धर्मसंकट खड़ा कर दिया था, वैसे ही एक समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया बताते हुए उसके खात्मे की जरूरत जताकर आइएनडीआइए को बगलें झांकने को मजबूर कर दिया था। उनसे उदयनिधि की बेहूदा टिप्पणी न तो निगलते बन रही थी और न ही उगलते। चूंकि सनातन धर्म के खात्मे की जरूरत जताने वाला बयान ग़ैर आपत्तिजनक था, इसलिए आइएनडीआइए के कई घटकों के नेताओं को दबे-छिपे स्वरों में उदयनिधि की नसीहत देनी पड़ी। ऐसी ही नौबत तब आई थी, जब कुछ तथाकथित सेक्युलर और समाजवादी नेताओं ने रामचरितमानस के खिलाफ टिप्पणियां करनी शुरू कर दी थीं। अभी हाल में महाकुंभ को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी भी विपक्षी गठबंधन के नेताओं के लिए मुसीबत बन गई थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो खरगे की टिप्पणी की परवाह न करते हुए संगम में डुबकी लगाना भी पसंद किया। इनमें कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी थे।

भारत में सेक्युलरिज्म की जैसी विकृत अवधारणा अपना ली गई है, उसके चलते खुद को सेक्युलर कहने वाले लोगों की ओर से औरंगजेब सरीखे आक्रांताओं का महिमामंडन करना, सनातन धर्म और उसकी परंपराओं का दकियानूसी बताना आवश्यक हो जाता है। इसी कारण कथित सेक्युलर दलों की ओर से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का विरोध होता रहा। इस विरोध का नतीजा यह हुआ कि सेक्युलरिज्म की पोल खुल गई और यह प्रमाणित हो गया कि वह छद्म सेक्युलरिज्म है। यदि आज कोई नेता यह नहीं कहता कि वह सेक्युलरिज्म की रक्षा के प्रति समर्पित है तो इसी कारण की वह एक हेय शब्द बन गया है। इसी छद्म सेक्युलरिज्म के चलते तीन तलाक जैसी कुरीति को प्रतिबंधित करने की पहल का भी विरोध किया गया। यह किसी से छिपा नहीं कि आइएनडीआइए के समक्ष कई तरह के राजनीतिक संकट हैं और दिल्ली विधानसभा चुनावों के समय यह तब अच्छी तरह से उजागर भी हुआ था, जब सपा और तृणमूल कांग्रेस आप के समर्थन में उतर आई थीं। इससे यदि कुछ स्पष्ट हुआ था तो यही कि आइएनडीआइए घटकों की दिली ख्वाहिश यही है कि गठबंधन की एकजुटता के नाम पर कांग्रेस उन राज्यों में भी कमजोर बनी रही, जो कभी उसके मजबूत गढ़ थे। कांग्रेस अपने इन गढ़ों में फिर से अपनी जड़ें जमाना चाहती है। यह उसके सहयोगी दलों को पसंद नहीं। कुल मिलाकर आइएनडीआइए के घटकों में आपसी विश्वास की कमी के चलते तो खटपट होती ही रहेगी, जब-जब कोई उदयनिधि सनातन धर्म को कोसेगा या फिर कोई अबू आजमी औरंगजेब का गुणगान करेगा तो भी उसका संकट बढ़ेगा, क्योंकि उसके नेता छद्म सेक्युलरिज्म को छोड़ने को तैयार नहीं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अहंकार से मुक्ति

आत्मशुद्धि अहंकार की भावना को त्यागे बिना संभव नहीं है, जबकि सत्य यह है कि अहंकार एक परछाई की भांति व्यक्ति के साथ लगा रहता है। एक हृदय से दूसरे हृदय तक जो राह जाती है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है अहंकार। इसे से उपजा कथित श्रेष्ठता का बोध हमें परतंत्र बनाए रखता है। जब तक हम किसी से अपनी तुलना करने में उलझे हैं, तब तक हम स्वाधीन नहीं हैं। अनजाने ही हमने अपने लिए एक सापेक्षता गढ़ ली और हर क्षण स्वयं को श्रेष्ठ समझने या सिद्ध करने में जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करने में लगे हैं।

अहंकार का त्याग कठिन है, किंतु यदि थोड़े से प्रयासों से कुछ सीमा तक चित्तशुद्धि संभव है। कुछ उपायों का निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा जैसे कि प्रथमतः दूसरों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना। आज जिस भली स्थिति में आप हैं, कल दूसरा भी वहीं होगा। आप आगे नहीं हैं, बस आपने थोड़ा पहले यात्रा शुरू कर दी। अहंकार को तिरोहित करने के लिए दूसरा आवश्यक बिंदु है कृतज्ञता। ईश्वरप्रदत्त हर सुख के लिए आभारी रहें, कर्मों का सुफल अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं दिया गया। हमें हर उस व्यक्ति के प्रति भी आभारी होना चाहिए जो हमारे जीवन में आया। अच्छी या बुरी जैसी भी सीख हमें मिली, हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक बनी। तीसरा आवश्यक बिंदु है सेवा। सेवा न तो उपकार के भाव से हो, न ही दास भाव से। मात्र सखा भाव हृदय को आलोकित करे, यह समझकर कि मैं एक पायदान ऊंचे पर था, मैंने हाथ बढ़ाकर अपने एक मित्र को भी ऊपर बुला लिया। मुक्ति के मार्ग पर हम सब सहयात्री ही तो हैं। कल किसी के हाथ और साथ की आवश्यकता हमें भी होगी। 'मुझमें अहंकार है' यह स्वीकार करना, फिर यह भाव लाना कि मैं इसे कम करने का प्रयास कर रहा हूं, यही प्रगति का सूचक है।

दिवंकल तोमर सिंह

भविष्य की ऊर्जा बनता ग्रीन हाइड्रोजन

सुधीर कुमार

ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के विकास में सहायक है

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग बढ़ती जा रही है। 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य के निमित्त दुनिया के कई देश ग्रीन हाइड्रोजन की भविष्य की ऊर्जा क्रांति के रूप में देख रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के विकास में सहायक है। यह सतत विकास को बढ़ावा देकर पृथ्वी को कार्बन-मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है।

भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए व्यापक निवेश की रूपरेखा तैयार की है। देश में 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन संचालित है। इसके तहत वर्ष 2030 तक पांच मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। गौरतलब है कि भारत ने 2070 तक 'नेट जीरो' हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन न सिर्फ शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनेगा, बल्कि ग्रह के कार्बन-मुक्तीकरण में भी सहायक साबित होगा। ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन की दो विधियां लोकप्रिय हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कही जाने वाली पहली प्रक्रिया के तहत सबसे पहले जल के अणुओं को हाइड्रोजन और आक्सीजन में विभाजित करने के लिए सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नवीकरणीय स्रोतों से बिजली प्राप्त करने के कारण ईंधन बनाने की यह प्रक्रिया कार्बनमुक्त में कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जित करने के स्थान पर केवल जलवाष्प उत्सर्जित करता है। इससे इस स्वच्छ ईंधन का जलवायु परिवर्तन में कोई खास योगदान नहीं रहता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय स्रोतों के प्रयोग से प्रति वर्ष 830 मिलियन टन कार्बन डाईआक्साइड को बचाना संभव हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की दूसरी विधि में बायोमास का गैसीकरण करके ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन किया जाता है। अपशिष्ट बायोमास का उपयोग करके उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन किसानों और स्थानीय समुदायों के लिए अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्रदान करता है।

हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जा सकता है। हालांकि उच्च उत्पादन लागत और हाइड्रोजन के उत्पादन में अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक ऊर्जा की खपत जैसी चिंताओं को दूर करना भी आवश्यक है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

भाषा पर होती भड़काऊ राजनीति

कृपाशंकर चौबे ने अपने आलेख 'भाषा पर भड़काने वाली राजनीति' में सही उल्लेख किया गया है कि हिंदी का विरोध देश की एकता के लिए घातक है। दरअसल 1968 में बनी त्रिभाषा फार्मूला नीति को के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित आयोग ने बरकरार रखते हुए हिंदी की अनिवार्यता समाप्त कर दी। इसमें मातृभाषा और अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई भी एक भाषा हो सकती है। फिर ऐसी ओछी राजनीति की क्या जरूरत है? हिंदी के कारण इसको अनेक बोलियां लुप्तप्राय हो गईं, क्या ऐसा संभव है? इन बोलियों के कारण हिंदी और अधिक समृद्धि हुई है। दरअसल नई शिक्षा नीति के विरोध के लिए भाषा को माध्यम बनाया जा रहा है। इससे हिंदी कमजोर नहीं होगी, अपितु तमिलनाडु की मातृभाषा कमजोर होगी। अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ेगा, जबकि विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार के कारण हिंदी सीखने को बढ़ावा दे रही हैं। फिर चुनावी लाभ के लिए शिक्षा नीति और भाषा को आधार बनाकर भावनाओं की राजनीति के दिन अधिक दिनों तक नहीं चल सकते हैं। 21वीं सदी की तमिलनाडु की जनता ऐसी राजनीति के फेर में फंसने वाली नहीं है। एमके स्टालिन को यह बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह मातृभाषा तमिल में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर जोर देने की बात कह चुके हैं।

मुकेश कुमार मनन, पटना

हास्यास्पद बयान

तमिलनाडु में अगले वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कितना हास्यास्पद है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन परिसीमन के नाम पर जनसाधारण से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। जिससे राज्य को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। जबकि सत्य यह है कि बिना जनगणना के परिसीमन का कार्य असंभव है। जनगणना का कार्य अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। वैसे भी तमिलनाडु में अजन कोई अच्छा जन्म लेता है तो उसका वोट का अधिकार आज से 18 साल के बाद आएगा। तब नेतानाथ परिसीमन के नाम पर अनर्गल और भड़काऊ राजनीति क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही तमिलनाडु सरकार त्रिभाषा फार्मूले के नाम पर हिंदी भाषा का विरोध कर रही है। इसके पीछे उसका जनसाधारण को दिग्भ्रमित कर स्तरहीन राजनीति और जनभावनाओं को उद्वेलित करने का खोष अधिक लगता है। तमिलनाडु में डीएमके के कुछ सांसदों के शैक्षणिक संस्थान हैं, क्या उन संस्थानों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती? निःसंदेह हिंदी और संस्कृत भाषा का देश के सभी राज्यों में सम्मान होना चाहिए। पुष्पा-2 का प्रसिद्ध डायलाग 'पुष्पा नाम समझकर फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं' हिंदी भाषा में होने की वजह से ही जबरदस्त ख्याति प्राप्त की। निःसंदेह हिंदी भारत की राजभाषा (आधिकारिक भाषा) है, जिसे संविधान में देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। डीएमके द्वारा हिंदी भाषा के विरोध पर कांग्रेस की चुप्पी राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को उजागर करती है। कहीं डीएमके पार्टी सत्ता विरोधी लहर का शिकार तो नहीं बनने जा रही? जिससे हिंदी भाषा के विरोध के नाम पर निष्प्रभावी किया जा सके।

दीपक गौतम, सोनीपत

शिक्षा नीति का बेतुका विरोध

'शिक्षा नीति पर रार' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। आज तमिलनाडु की सरकार तथा विपक्ष द्वारा दलगत राजनीति से प्रेरित होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के क्रियान्वयन पर तथ्यहीन और बेतुका विरोध किया जा रहा है। एनईपी में त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से दो भारतीय मूल भाषाओं को सीखने की अनिवार्यता से छात्रों को भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा से और अधिक जोड़ने की कवायद है। भाषा के अध्ययन से ही आप अपने साहित्य, नैतिक शिक्षा, काव्य संकलनों को समझते हैं। जो आधुनिकता की दौड़ में भागते समाज को अपनी जड़ों से जुड़े रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है। विकसित भारत बनाने हेतु क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद की जंजीरों को तो हमें काटना होगा।

पीयूष शंकर गर्ग, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

160 अरब डालर तक पहुंच सकता है वैश्विक अंतरिक्ष बाजार, अगले दस साल में। भारत सरकार की मंशा है कि इसमें देश की हिस्सेदारी 44 अरब डालर या इससे भी अधिक हो। फिलहाल यह हिस्सेदारी 13 अरब डालर है।

अजकल

अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियां

अंतरिक्ष और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे बेहद जटिल क्षेत्रों में भी निजी कंपनियों के सहयोग और समन्वय की राह खुलने लगी है। इस कड़ी में हमारे देश में एक पहल एलएंडटी की ओर से हो रही है। कंपनी द्वारा हाल में कहा गया है कि वह भारत के एयरोस्पेस में अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि उसका उद्देश्य निजी अंतरिक्ष यानों का निर्माण करने और उन्हें स्पेस में पहुंचाने के काम में हिस्सेदारी हासिल करना है

मानव जाति के लिए हितकारी साबित होता अंतरिक्ष अन्वेषण। फाइल

अभिषेक कुमार सिंह
सस्था टेलीपरफार्मेंस से संबद्ध

वैसे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) बीते एक दशक से अपने बहुत से कार्यों में निजी कंपनियों का सहयोग लेता रहा है। अंतरिक्ष की सहयोगी तकनीकों और राकेट आदि से जुड़े कलपुर्जों के निर्माण और सप्लाई के लिए इसरो ने काफी पहले ही निजी भारतीय कंपनियों से सहयोग लेना शुरू कर दिया था, लेकिन तीन साल पहले 2022 में इसकी एक विधिवत शुरुआत मिशन 'प्रारंभ' के साथ हुई। इसके तहत दो 18 नवंबर, 2022 को सबसे पहले इसरो की मदद से हैदराबाद के एक अंतरिक्ष स्टार्टअप- स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी राकेट विक्रम-एस का सफल प्रक्षेपण किया। अब कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) सहयोग की इस गंगा को नए मुकाम पर ले जाना चाहती है। कंपनी के अनुसार उसका इरादा एयरोस्पेस के क्षेत्र में अपने कारोबार का विस्तार करना है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी- नासा के साथ अरबपति कारोबार एलन मस्क जिस तरह से अपनी अंतरिक्ष कंपनी- स्पेसएक्स के जरिये अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) ले जाने और वहां से लाने और अन्य जटिल अभियानों में संलग्न हैं, लगता है कि उसी तरह से एलएंडटी भी इस क्षेत्र की संभावनाओं का लाभ उठाना चाहती है।

कमाई और दक्षता है असली कसौटी : अगले एक दशक में भारत का लक्ष्य देश के वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र का मूल्य 44 अरब डालर तक बढ़ाना है, तब ऐसी पहलकदमियों की सख्त जरूरत है। एक बड़ी निजी कंपनी की अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भागीदारी एक उल्लेखनीय बदलाव भी ला सकती है। हालांकि इसमें क्षेत्र विशेष में दक्षता की भी बड़ी भूमिका है। अभिप्राय यह है कि अगर एलएंडटी को इस सहयोग के लिए चुना जाता है, तो इसमें उसकी विशेषज्ञता और कारोबार के आकार की भी मुख्य भूमिका रहेगी। उल्लेखनीय है कि कमाई के हिसाब से भारत के रक्षा उद्योग में एलएंडटी की गिनती सबसे बड़ी निजी कंपनियों में होती है। यही नहीं, तमिलनाडु के कोयंबटूर में सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर यह कंपनी इस समय पीएसएलवी यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का निर्माण भी कर रही है। निजी कंपनी के सहयोग से बनने वाला यह देश का पहला अंतरिक्ष यान (पीएसएलवी) होगा। इसरो के लिए पीएसएलवी की प्रतिष्ठा लगभग वही है, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी के लिए एलन मस्क की कंपनी द्वारा बनाए जा रहे फाल्कन-9 राकेट की है।

अंतरिक्ष में निजीकरण पर सवाल : यहां एक अहम सवाल है कि आखिर क्यों अंतरिक्ष अन्वेषण और पर्यटन जैसे बेहद कठिन और संवेदनशील अभियानों में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका एक पहलू इससे समझा जा सकता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक उद्देश्य वैज्ञानिक और राष्ट्रीय हितों (जैसे कि सुरक्षा, मौसम संबंधी जानकारी जुटाना आदि) का पोषण करना होता है। इसमें राष्ट्र सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील मुद्दे भी शामिल होते हैं, जिसमें कोई भी चूक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है तो इसका उत्तर यह है कि अव्वल तो ऐसे नाजुक मसलों में किसी निजी कंपनी का दखल नामुमकिन होगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ वही काम सौंपने की योजना है जिनमें किसी संवेदनशील सूचना का आदान-प्रदान जरूरी नहीं है, बल्कि इस साझेदारी के दो अलग उद्देश्य हैं। पहला, वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का दोहन करना और दूसरे, सरकारी महंगे अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संचालन के लिए बाहरी (निजी) पूंजी हासिल करना, ताकि देश अपने आर्थिक संसाधनों का आम जनता से जुड़े अन्य महत्व की योजनाओं में इस्तेमाल कर सके। अनुमान है कि अगले दस साल में वैश्विक अंतरिक्ष बाजार 160 अरब डालर तक पहुंच सकता है। भारत सरकार की मंशा है कि इसमें हमारे देश की हिस्सेदारी 44 अरब डालर या इससे भी अधिक हो सके। फिलहाल यह हिस्सेदारी सिर्फ 13 अरब डालर है, जो अंतरिक्ष बाजार के मूल्य को देखते हुए बहुत कम है। इस हिस्सेदारी में बढ़ोतरी दो चीजों पर निर्भर करती है। पहली, भारत उपग्रह प्रक्षेपण और सुदूर अंतरिक्ष अन्वेषण का काम उसी दक्षता और कामयाबी की ऊंची दर के साथ कर सके, जैसे नासा या अन्य यूरोपीय स्पेस एजेंसियां करती हैं। दूसरी, भारत ये काम बेहद प्रतिस्पर्धी कीमत पर करता रहे। गौरतलब है कि इन दोनों ही मोर्चों पर इसरो का रिकार्ड शानदार रहा है। बेहद कम कीमत पर और सर्वाधिक सफलता की दर से उपग्रहों के प्रक्षेपण के बल पर इसरो आज इस बाजार का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। निजी कंपनियों की साझेदारी से इसरो के विस्तार और कमाई, दोनों में भरपूर इजाफा संभव है।

खर्च घटाना भी एक मकसद : भारत और इसरो के लिए राजस्व कमाने का एक और जरिया उपलब्ध हो रहा है। यह है अमीरों को अंतरिक्ष की सैर के लिए आकर्षित करना। जिस प्रकार नासा ने स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के सहयोग से अंतरिक्ष की सैर के खुबह को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। इंसान उस अंतरिक्ष को छूकर एक तसल्ली पाना चाहता है, जिसका विस्तार अरबों-खरबों किलोमीटर में है। हालांकि मौजूदा अंतरिक्षयानों के लिए मुमकिन नहीं है कि वे अपने साथ इंसान को चंद्रमा से पार ले जाकर वापस पृथ्वी पर सही-सलामत ला सकें। इसलिए अभी की स्थितियों में स्पेस कही जाने वाली सरहद को छूना और चंद्रमा तक किसी मिशन को सही-सलामत पहुंचाना ही एक बड़ी उपलब्धि है।

ज्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि इंसानों को अंतरिक्ष कहलाने वाली पृथ्वी की निचली कक्ष (सबआर्बिट) तक ले जाया जाए। अभी तक यह सारा काम सरकारी स्पेस एजेंसियां जैसे कि अमेरिका की नासा आदि ही करती रही हैं, पर अंतरिक्षयात्राओं और अनुसंधान पर बढ़ रहे खर्च के कारण सरकारें इस काम से हाथ खींचने लगी हैं। इसकी वजह यह बताई गई है कि अंतरिक्ष से ऐसी नई उपलब्धियों की संभावनाएं खत्म गई हैं जिनसे कमाई का कोई रास्ता खुलता हो। अंतरिक्षीय पिंडों से खनिजों और बहुमूल्य धातुओं के खनन की बातें अक्सर कही-सुनी जाती हैं, लेकिन वह काम इतना खर्चीला और झंझट भरा है कि कोई सरकार इसकी शुरुआत कर अपने हाथ नहीं जलाना चाहती है।

शीतयुद्ध के काल में अंतरिक्ष अनुसंधान के बहाने अंतर-महाद्वीपीय (बैलिस्टिक) मिसाइलों के विकास का जो काम किया गया, अब वे सारे मकसद भी हासिल हो चुके हैं। ऐसे कार्यक्रमों के जरिये महाशक्ति बनने का जो उद्देश्य अमेरिका हासिल करना चाहता था, वह भी उसे मिल चुका है। अब राकेट प्रक्षेपण और अंतरिक्ष अनुसंधान का ज्यादातर कामकाज भारत-चीन जैसे एशियाई देशों की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिन्हें अभी इन क्षेत्रों में अमेरिका-रूस के मुकाबले अपनी काबिलियत साबित करनी है। इन कारणों के मद्देनजर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण यूरोपीय स्पेस एजेंसी और इसरो से करवाती है और बाकी बचे ज्यादातर काम निजी कंपनियों के हवाले कर दी है। खास तौर से अंतरिक्ष भ्रमण (सैर या टूरिज्म) से लेकर सुदूर अंतरिक्ष की खोज तक के लिए वह सरकारी पैसे के इस्तेमाल से बचना चाहती है।

अंतरिक्ष पर्यटन का पूरा होता सपना

अंतरिक्ष अनुसंधान और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निजी उद्यमों के योगदान से अंतरिक्ष एक बार फिर इंसान के सपनों की नई मंजिल बन गया है। एलन मस्क की स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की और की जा रही पहलकदमियों को देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों में यह ललक जाग उठी है कि किसी तरह अंतरिक्ष की सैर के सपने को एक आम स्वप्न में बदल दिया जाए। पांच साल पहले (2020 में) अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की एक सथ नागरिकता रखने वाले अरबपति एलन मस्क की कंपनी-स्पेसएक्स दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई, जो अपने राकेट से दो अंतरिक्ष यात्रियों को आइएसएस तक सफलतापूर्वक ले गई थी। स्पेसएक्स का ताकतवर राकेट फाल्कन-9 स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल लेकर कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ा था। उसमें राबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले नामक दो अंतरिक्षयात्री थे।

उससे पहले जब कभी अंतरिक्ष यात्राओं की बात उठी तो कहा जाता रहा कि बिना सरकारी एजेंसियों के यह काम संभव नहीं है। असल में इस यात्रा में अत्यधिक खतरों, खर्च और यात्रियों के कौशल के अलावा इन्हें संयन कराने वाले संगठनों की विशेषज्ञता का इतना ज्यादा महत्व है कि प्राइवेट एजेंसियां प्रायः इसमें हाथ डालने से बचती रही हैं। लिहाजा पहले ऐसे ज्यादातर कारनामे सरकारी स्पेस एजेंसियों की मदद से ही हो सके। जैसे 28 अप्रैल, 2001 को स्पेस कंपनी- स्पेस एडवेंचर ने अमेरिकी पर्यटक डेनिस टीटो को रूसी राकेट सोयूज टीएम-32 और आइएसएस ईपी-1 नामक यान से आइएसएस पहुंचाया था। टीटो दुनिया के ऐसे पहले टूरिस्ट बने थे, जिन्होंने पैसे खर्च करके अंतरिक्ष की यात्रा की थी। दावा किया जाता है कि टीटो ने उस यात्रा के लिए 20 मिलियन डालर चुकाए थे। टीटो के बाद दक्षिणी अफ्रीकी व्यवसायी मार्क शटलवर्थ (25 अप्रैल, 2002), अमेरिकी पूंजीपति ग्रेग ओल्सन (एक अक्टूबर, 2005), ईरानी मूल की पहली महिला- अनुशेह अंसारी (18 सितंबर, 2006) और एक साफ्टवेयर आर्किटेक्ट चार्ल्स सिमोनी (7 अप्रैल, 2007) ने पैसे खर्च करके अंतरिक्ष की सैर का आनंद लिया। निजी तौर पर स्पेस भ्रमण को जाने वाले लोगों में प्रायः सभी बेहद दौलतमंद थे।

–अभिषेक कुमार सिंह

खरी-खरी

नेताजी और दिल की बात

डा. प्रदीप मिश्र

औरंगजेब पर कुछ बोलने के लिए पत्रकार, नेताजी को परेशान कर रहे थे, लेकिन उनका तजुर्बा मौन रहने को ही उचित मान रहा था। बारबार 'नो कमेंट' कहने के बावजूद पत्रकार उनसे कमेंट कराने पर उतारू थे। उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा, 'क्या बोलूं?' 'जो आपका दिल बोले।'

'मेरा दिल तो बोल रहा है कि तुझे सेक्रेटरी पद से बर्खास्त कर दूं। शर्म नहीं आई मुझसे दिल की बात बुलवाते हुए?' नेताजी ने सेक्रेटरी को धमकाया, लेकिन सेक्रेटरी, चौबीस कैरेट वाला शुभचिंतक था। उसने बिना डरे कहा, 'नेता को जब क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं वाली स्थिति में झूलना पड़े, तो उसे तत्काल अपने दिल की बात जुबां पर लानी चाहिए।' 'बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। मेरे लिए औरंगजेब, राजा या आदर्श नहीं, बल्कि एक मुद्दा है। और राजनीति में किसी मुद्दे पर बोलना खिंची हुई रस्सी पर चलने जैसा होता है। संभलकर नहीं चले तो गिरने में वक्त नहीं लगता।'

'तो दिल की बात कहिए न?' सेक्रेटरी, दिल पर अड़ा था। 'फिर दिल की बात? राजनीति में जिसे अपनी दुर्गति करानी होती है, वही दिल की बात जुबां पर लाता है। आदर्श नेता अपने दिल की बात कभी जुबां पर नहीं लाता। उसकी जुबां पर वही बात आती है, जो न उसके दिल में होती, न दिमाग में।'

'औरंगजेब आपके दिल में है या दिमाग में?' 'दोनों जगह नहीं।' 'कहीं तो होगा?' सेक्रेटरी मानने को तैयार नहीं था। हारकर नेताजी ने खिड़कियां-दरवाजे बंद करवाए और फुसफुसाते हुए बोले, 'औरंगजेब मेरी राजनीति में है। वह अच्छा था, बुरा था। क्रूर या कोमल था। मंदिर तोड़क था, निर्माणक था मैं नफा-नुकसान देखकर बोलूंगा?

जो फायदा कराए, नेता की जुबां पर वही आए।' 'लेकिन आपने इतिहास का अध्ययन किया होगा? आपके अपने विचार भी होंगे?' 'मैं अध्ययन-शून्य था, इसलिए नेता बन। और विचारों को तिलांजलि दी तो आज राजनीति के शिखर पर हूं।' कहकर नेताजी ने सेक्रेटरी की चपरासी के रूप में तैनाती का आर्डर जारी कर दिया।

पोस्ट

बात केवल भारत के आइसीसी ट्राफी जीतने की नहीं, बल्कि जीतने के अंदाज की भी है। हमने एक भी मैच गंवाए बिना खिताब अपने नाम किया। पिछले छह वर्षों में आइसीसी स्पर्धाओं में भारत का जबरदस्त रिकार्ड रहा है और वे सभी मैच दुबई में ही नहीं खेले गए।
संजय मांजरेकर@sanjaymanjrekar

भारत में सभी धर्मों के लोग त्योहार मिलजुल कर मनाते आए हैं। दीवाली, होली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस आदि मनाते समय एक-दूसरे का धर्म नहीं देखा जाता। इनकी छुट्टियां धर्म देख कर नहीं दी जातीं, बल्कि सभी को मिलती हैं। ऐसे में होली को लेकर आए बयान दुर्भाग्यपूर्ण है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जिन पर्यटन स्थलों पर अधिक पर्यटक आते हैं, वहां टूरिस्ट पुलिस की तैनाती होनी चाहिए जो सामान्य पुलिस से अलग हो। देश में टूरिस्ट पुलिस की सक्रियता को साकार किया जाना समय की मांग है। जब तक राज्य सरकारें इसका महत्व नहीं समझतीं, केवल पुलिस विभाग की पहल अस्थायी और अधूरी सिद्ध होगी।
अमरेक विज@ipsvijrk

हरियाणा डायरी

अनुराग अग्रवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, हरियाणा

सेनापति बिन बिखरती कांग्रेस

इस समय हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। 90 सदस्यीय विधानसभा में 37 विधायकों वाली कांग्रेस बिना विधायक दल के नेता के बजट सत्र की कार्यवाही में भागीदारी कर रही है। इससे पहले नवंबर में भी एक बार कांग्रेस बिना विधायक दल के मानसून सत्र में भागीदारी कर चुकी है। कांग्रेस को लग रहा था कि बजट सत्र से पहले-पहले विधायक दल के नेता की घोषणा हो जाएगी, मगर बजट सत्र आरंभ होने के दिन सात मार्च तक भी ऐसा नहीं हुआ। नतीजतन सभी कांग्रेस विधायकों को इसके बिना ही विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सेदारी करनी पड़ी। तीसरी बार सत्ता में आई भाजपा के सामने कांग्रेस विधायक ऐसे बैठे थे, जैसे बिना सेनापति के कोई सेना युद्ध के मैदान में पहुंच जाए और उसके सैनिकों को समझ न आए कि उन्हें सामने वाली सेना से कैसे लड़ना है।

पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे। उन्हीं के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। टिकटों के बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार करने तक हुड्डा का कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव के साथ टकराव चलता रहा। कुमारी सैलजा नाराज होकर घर बैठ गईं, जो भाजपा के लिए फायदेमंद रहा। कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी का ही नतीजा रहा कि सत्ता के करीब तक पहुंचकर भी कांग्रेस चुनाव हार गई। संकट यहां तक बढ़ गया कि अब कांग्रेस विधायक दल का नेता किसे बनाएं? हरियाणा में हुड्डा को कांग्रेस माना जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी राजनैतिक ताकत दिखाते हुए हाईकमान को मजबूत पकड़ का अहसास कराया और अब दोनों के हस्तक्षेप की वजह से ही विधायक दल के नेता की घोषणा नहीं हो पा रही है, उससे आने वाला समय कांग्रेस के लिए काफी पेचीदा रहने की आशंका बन रही है।

हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को अब तक नहीं मिला विधायक दल का नेता। फाइल

हरियाणा में चुनाव जीतकर आए 37 कांग्रेस विधायकों में हालांकि कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक विधायक काफी कम हैं, लेकिन फिर भी सैलजा एवं सुरजेवाला चाहते हैं कि कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद पर हुड्डा के बजाय किसी दूसरे सर्वमान्य नेता को जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हुड्डा ने सैलजा एवं सुरजेवाला की टिकण वितरण में एक नहीं चलने दी थी। कई विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं, जहां बागी उम्मीदवारों की वजह से कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। यदि वहां हुड्डा अथवा डीपेंद्र बागियों को मनाने चले जाते तो स्थिति कुछ दूसरी होती। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की आस के कारण हुड्डा और डीपेंद्र ने बागियों को समय रहते मनाने की कोई कोशिश नहीं की। चुनाव में हार के बाद ये सारी बातें अलग-अलग कमेटियों तथा नेताओं के माध्यम से हाईकमान के पास पहुंचीं तो अब स्थिति काफी उलझ चुकी है।

कांग्रेस हाईकमान की ओर से दीपक बाबरिया को हटाकर बीके हरिप्रसाद को नया पार्टी प्रभारी बनाया जा चुका है। नए प्रभारी की ओर से हरियाणा के नेताओं से बातचीत के बाद विधायक दल के नेता के बारे में अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी गई है, लेकिन बजट सत्र तक भी हाईकमान द्वारा विधायक दल के नेता का नाम घोषित नहीं करने का मतलब साफ है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे नहीं चाहते कि हरियाणा में दौबारा से हुड्डा के हाथों में पार्टी की कमान सौंपी जाए। अब सवाल खड़ा हो रहा कि हुड्डा नहीं तो दूसरा कौन? सुरजेवाला और सैलजा समर्थक आधा दर्जन विधायकों में कोई ऐसा नहीं है, जिसे विधायक दल के नेता का दायित्व सौंपा दिया जाए। हालांकि विधायक दल के नेता के लिए थानेसर के कांग्रेस विधायक एवं पूर्व स्पीकर असोक अरोड़ा, कांग्रेस विधायक दल के पूर्व उप नेता चौधरी आफताब अहमद, रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा, झज्जर की विधायक एवं पूर्व मंत्री गीता भुक्कल और पूर्व स्पीकर डा. रघुबीर कादियन के नाम लिए जा रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं का मानना है कि बजट सत्र में बिना नेता के कार्यवाही में शामिल होने से पार्टी की काफी छिछालेदर हो रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट सत्र में जिस तरह से सत्ता पक्ष के साथ मोर्चा संभाला है, उससे लग रहा है कि हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के नेता पद पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनके साथ-साथ असोक अरोड़ा, गीता भुक्कल, बीबी बत्रा और आफताब अहमद ने जिस गर्मजोशी के साथ जनता के मुद्दे उठाए हैं, उनके माध्यम से वे कांग्रेस हाईकमान को यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि जरूरत पड़ी तो हम भी नेतृत्व करने को तैयार हैं। विधानसभा का बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान को उम्मीद है कि बजट सत्र के दौरान भी विधायक दल का नेता घोषित किया जा सकता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या रोहित शर्मा का कटक मुकाबलों से रिलेयर न होने का फैसला सही है?

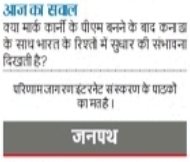

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या मार्क कार्नी के पीएम बनने के बाद कनाडा के साथ भारत के रिश्ते में सुधार की संभावना दिखती है?

दैनिक जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

उन्नति कितनी कर रहा देखो पाकिस्तान,
ट्रेन हाइजैक हो रही जाय वतुर्ध स्तान।
जाय बलुचिस्तान दबाया है हक जिनका,
वे वसूल इक रोज करेंगे तिनका-तिनका।
बुरा किया है कर्म बुरों ही पाएगा गति,
बोया है आतंक इसे में होगी उन्नति!
– ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

इतिहास की न हो गलत व्याख्या

औरंगजेब जैसे शासकों का महिमामंडन करने से हम उन अत्याचारों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो उन्होंने हमारे समाज पर किए

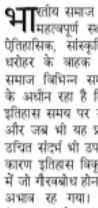
आकृश अवस्थी
सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू

भारतीय समाज में प्रतीकों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्रतीक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के वाहक होते हैं। भारतीय समाज विभिन्न समयकाल में दूसरों के अधीन रहा है जिस कारण अपना इतिहास समय पर न लिखा जा सका और जब भी यह प्रयास किए गए तो उचित संदर्भ भी उपलब्ध नहीं थे। इस कारण इतिहास विकृत हुआ, भारतीयों में जो गौरवबोध होना चाहिए था उसका अभाव रह गया। हाल में महाराष्ट्र विधानसभा से सपा के एक विधायक अबू आजमी को औरंगजेब पर दिए बयान की वजह से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद से यह बहस और व्यापक हो गई है। भारतीय इतिहास में औरंगजेब एक ऐसा शासक है, जिसको लेकर लगातार पुनर्व्याख्या होती रही है। कुछ लोग उसे कट्टर इस्लामी शासक मानते हैं, जिसने हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, तो कुछ एक कुशल प्रशासक मानते हैं, जिसने मुगल साम्राज्य को चरम सीमा तक पहुंचाया। इन दोनों ही विचारों को इतिहास के तराजू पर तौलना चाहिए जिसमें भारतीय दृष्टिकोण भी सम्मिलित हो।

जो लोग औरंगजेब को सहिष्णुता का प्रतीक मानते हैं, उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि मात्र नौ वर्ष के फतेह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा देना क्या न्याय था? क्या अपनी ही बेटी जेब-उन-निसा को किले में कैद कर देना और वहां उसकी मृत्यु हो जाना पिता के प्रेम का प्रमाण था? औरंगजेब की कट्टरता 'मआसिर-ए-आलमगीरी' किताब में लिखे उसके नौ अप्रैल, 1669 को जारी फरमान से समझी जा सकती है, जिसमें उसने सभी हिंदू मंदिरों एवं शिक्षा-केंद्रों को नष्ट करने के आदेश दिए थे। इतिहासकारों का मानना है कि उसके बाद गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवदेव मंदिर, बद्रीनाथ का हथेश्वर मंदिर, उदयपुर में झीलों के किनारे बने तीन मंदिर, उज्जैन के आसपास के मंदिर समेत देश भर के सैकड़ों मंदिर ध्वस्त करा दिए गए। कट्टरपंथी सोच के कारण ही उसने हिंदुओं के त्योहारों एवं धार्मिक प्रथाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया था। 1679 में उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, कुंभ में आक्रमण कर हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया। यह सब सहिष्णुता की निशानी तो नहीं हो सकती है।

औरंगजेब ने तलवार के दम पर हिंदुओं का मतांतरण भी करवाया। इस्लाम न स्वीकार करने पर निर्दोष एवं निहत्थे हिंदुओं का कत्लेआम करवाने में संकोच नहीं किया। मतांतरण में उसने गुरु तेगबहादुर और उनके तीन अनुयायियों भाई मति दास, सती दास और दयाल दास को अत्यंत क्रूरता एवं निर्दयता के साथ मरवा दिया। इस्लाम स्वीकारने से मना करने पर संभाजी को अमानवीय यातनाएं दीं। क्या औरंगजेब यह सीमा विस्तार के लिए कर रहा था या फिर इस्लाम के प्रसर के लिए?

आज जब समाज में इन तथ्यों को सामने रख औरंगजेब की पुनर्व्याख्या का प्रयास किया जा रहा है तो कुछ वामपंथी इतिहासकार इसको इतिहास से छेड़छाड़ के रूप में देख रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है ऐसा प्रसारित कर रहे हैं। वे औरंगजेब की हिंसा को उचित ठहराने के लिए सम्राट अशोक और कश्मीर के शासक हर्ष का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अशोक को क्या कलिंग पर आक्रमण के लिए याद किया जाता है या उस हिंसा से उपजे उनके हृदय-परिवर्तन के लिए? इसी प्रकार वामपंथी इतिहासकार हर्ष, जिसे 'मूर्तिभंजक हर्ष' कहा जाता है, का हवाला देते हुए कहते हैं कि उसने जितने मंदिर तोड़े, उतने औरंगजेब ने नहीं, लेकिन भारतीय समाज ने हर्ष को कभी स्वीकार नहीं किया, न ही उसकी छवि सुधारने का प्रयास किया। जबकि औरंगजेब को सहिष्णु दिखाने का प्रयास इतिहास के साथ छल है।

इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने से समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी यदि हम अपने इतिहास के प्रतीकों को पुनर्स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम सामाजिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हिंदू समाज के प्रतीकों पर चल रही यह अंतर्कलह वैमनस्यता को जन्म दे रही है, जिससे समाज में कटुता बढ़ती जा रही है। भारतीय समाज को अपने गौरवशाली अतीत को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख भी होता है। जब हम अपने अतीत को गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं, तो हम अपनी संस्कृतिक विरासत को कमजोर करने का कार्य करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इतिहास को तटस्थता के साथ देखें और तथ्यों को उसी रूप में स्वीकार करें, जिस रूप में वे घटित हुए थे। समाज को यह विचार करना होगा कि क्या हम अपने ऐतिहासिक प्रतीकों को पुनर्स्थापित कर सकते हैं या नहीं। यदि हम अपने इतिहास को सही संदर्भों में नहीं रखेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भ्रम में रहेंगी। औरंगजेब जैसे शासकों का महिमामंडन करने से हम उन अत्याचारों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो उन्होंने हमारे समाज पर किए। यह केवल हिंदू-मुस्लिम विवाद का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी ऐतिहासिक चेतना का प्रश्न है।

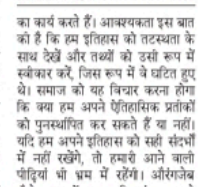
आक्रांताओं के महिमामंडन की बीमारी। फाइल

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 21

एमएसपी में जकड़ी प्रतिस्पर्द्धा

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देश की कृषि नीति का अनिवार्य अंग रहा है। इसके पीछे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसानों को कीमतों के जोखिम से बचाने जैसे नेक इरादे रहे हैं। लेकिन इसके कुछ अनचाहे परिणाम भी हैं जैसे फसलों की विविधता कम होना और देश के कुछ हिस्सों में पर्यावरण को नुकसान शामिल हैं। अब कृषि से होने वाली आय में इजाफे की जरूरत है मगर कुछ किसान समूहों की मांग मानकर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना अच्छा नहीं रहेगा। इससे सही मूल्य निकालने में दिक्कत आ सकती है और आगे चलकर उत्पादन और भी बिगड़ सकता है। इसके अलावा यह कृषि आय को सुरक्षित रखने का कारगर उपाय भी नहीं है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान का हाल में आया एक अध्ययन कहता है कि एमएसपी के लाभ कम किसानों तक ही पहुंच पाते हैं। अध्ययन में पता चला कि 15 फीसदी धान किसान और 9.6 फीसदी गेहूं किसान ही सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल हैं और वे भी बड़े किसान हैं। छोटे और सीमांत किसान देश का 53.6 फीसदी धान और 45 फीसदी गेहूं उगाते हैं मगर सरकारी खरीद में उनकी ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है। एमएसपी पर सरकारी खरीद में हिस्सेदारी और खेतों के आकार में सीधा संबंध इसलिए है क्योंकि छोटे और सीमांत किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसके अलावा अक्सर कम उत्पादन भी उनके हाथ बांध देता है।

एमएसपी से होने वाली दूसरी दिक्कतें हैं खजाने से भारी रकम निकल जामा, बहुत पानी खर्च कराने वाली फसलों का जरूरत से ज्यादा उत्पादन और भंडारण की नाकाफी व्यवस्था। कृषि आय सुधारने के लिए जरूरी है कि बाजार अच्छी तरह काम करें। इसमें बुनियादी ढांचे में निवेश और किफायती मूल्य श्रृंखला तैयार करना शामिल है ताकि खेत से निकली फसल के थाली तक पहुंचने में कीमत बहुत अधिक न बढ़े। कीमतों में उतार-चढ़ाव हमेशा किसानों के लिए जोखिम से भरा होता है और उन्हें इससे बचाने के लिए उस अध्ययन में भावांतर चुकाने की बात है। इसके तहत किसानों को बाजार में एमएसपी से जितनी कम कीमत मिलती है उस अंतर की भरपाई कर दी जाती है। इसका लक्ष्य एमएसपी नीति को खरीद से हटाकर आय का साधन बनाना है मगर इसका क्रियान्वयन भी दिक्कतों से भरा है। अतीत में मध्य प्रदेश भावांतर भुगतान योजना आजमा चुका है, लेकिन एक सीजन के बाद ही उसने इससे तौबा कर लिया। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का कहना है कि इस नीति से बाजार भाव और भी नीचे जा सकते हैं क्योंकि किसान तथा व्यापारी सांठगांठ कर बाजार मूल्य को एमएसपी से बहुत कम कर देंगे। इस तरह उन्हें अधिक भावांतर मिल जाएगा मगर सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ सकता है।

जाहिर है कि इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं। फिर भी भारत को निजी खरीद प्रोत्साहित करने, फसलों में विविधता लाने और कृषि शोध बढ़ाने की जरूरत है। कृषि जिंसों के क्षेत्र में डेरिवेटिव्स बाजार भी भागीदारों को बाजार की अनिश्चितता और कीमतों के जोखिम से बचाते हैं। भारत को मुक्त बाजार और मजबूत कृषि मूल्य श्रृंखला चाहिए, जहां उपभोक्ताओं की जेब से जा रही रकम का बड़ा हिस्सा किसानों को ही मिले। विशेषज्ञों ने कहा भी है कि इस क्षेत्र में वृद्धि मोटे तौर पर एमएसपी के दायरे से बाहर वाले उत्पादों से हो रही है। जरूरत यह है कि इन सफलताओं से सीखते हुए उत्पादन में मांग के मुताबिक बदलाव लाया जाए। मूल्य समर्थन और भावांतर भुगतान के जरिये सरकारें एक हद तक ही हस्तक्षेप कर सकती हैं मगर इस क्षेत्र को स्थायी मदद नहीं पहुंचाई जा सकती। कृषि बाजारों को व्यापार के लिए खोलने के बढ़ते दबाव के बीच सरकार समेत सभी अंशधारकों को प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के रास्ते तलाशने होंगे।

विनय सिन्हा

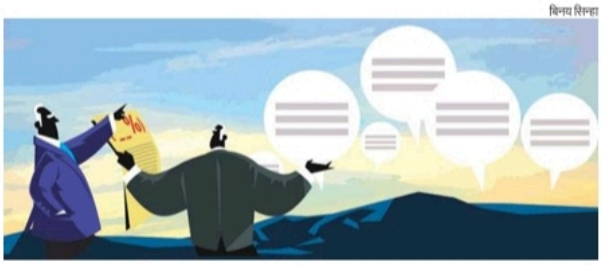

विधि निर्माण में तय हो नागरिकों की भूमिका

प्रभावी नीति निर्माण के लिए जरूरी है कि आम मशविरे के बिना बने कानून खत्म कर दिए जाएं। विस्तार से बता रहे हैं एम एस साहू और मल्लिका दांडेकर

इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट विनियमन पर खूब जोर रहा है। सरकार पहले लागू कई कानूनों और नियम-कायदों को वापस लेने पर विचार कर रही है। कायदे-कानून बनाते समय अगर सार्वजनिक सलाह-मशविरे पर जोर दिया गया होता तो यह कवायद नहीं करनी पड़ती। ढंग से मशविरा किया जाए तो नियमन न कम रहता है और न ही उसकी अति हो पाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि तार्किक, जरूरी और संतुलित उपाय ही लागू हों।

लोकतंत्र में नागरिक सर्वोपरि होते हैं और उनके पास महत्त्वपूर्ण अधिकार तथा दायित्व होते हैं। इनमें सबसे ऊपर हैं: मतदान का अधिकार तथा सार्वजनिक पदों के लिए होड़ करने का अधिकार। इसी से वे अपनी पसंद की सरकार बना पाते हैं। दूसरा, सरकार के निर्णयों और नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता ताकि सरकार नागरिकों की सामूहिक इच्छा के अनुसार ही काम करे। यदि सरकार तुरंत काम करने वाली होती है तो दूसरा अधिकार सुरक्षित रहता है और ऐसा नहीं करती है तो नागरिक पहले अधिकार का प्रयोग कर उसे हटा देते हैं।

कानून निर्माण में सार्वजनिक चर्चा दूसरे अधिकार का उदाहरण है। इससे पता चलता है कि सरकार नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रक्रिया में योगदान का नागरिक कर्त्तव्य भी इससे पुख्ता होता है। ऐसी भागीदारी कानून की वैधता बढ़ाती है, पारदर्शिता बढ़ाती है और सरकार तथा नागरिकों के बीच भरोसा भी बढ़ाती है। भागीदारों से शुरू में ही राय ले ली जाए और उनके हितों का ध्यान रखा जाए तो कानून वापस लेने, उसके लटकने या लागू होने में बाधा आने का खतरा बहुत कम हो जाता है। नागरिक भागीदारी की अहमियत समझते हुए कई लोकतंत्रों ने सार्वजनिक सलाह-मशविरे को विधायी प्रक्रिया का आवश्यक अंग बना दिया है।

भारत में जन भागीदारी का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, जो संविधान निर्माण के समय भी दिखा था। कई कानून कहते हैं कि उनके तहत बनने वाले नियम-कायदों को पहले प्रकाशित कर अंशधारकों की राय ली जानी चाहिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2002 में ही देश की विधायी व्यवस्था में सार्वजनिक मशविरा शुरू किया था। डिजिटल प्लेटफॉर्म आने से यह काम बहुत आसान हो गया है और अधिक संख्या में लोग जल्दी से भागीदारी कर लेते हैं। सरकार ने 2014 की अपनी नीति के जरिये इसे औपचारिक जामा पहना दिया और अब सभी नियम-कायदों के मसौदे पर सार्वजनिक चर्चा जरूरी हो गई है। 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कानून निर्माण में अंशधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात दोहराई।

तब से सार्वजनिक मशविरे का महत्त्व बढ़ा है। 2023-24 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय क्षेत्र के जरूरी नियमन के लिए सार्वजनिक मशविरे का महत्त्व समझाया। प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) अधिनियम 2023 कहता है कि नियमन तैयार करते समय नियामकों को अंशधारकों से मशविराक करना ही होगा और इसका तरीका भी बताया गया है। कई नियामकों ने स्वेच्छा से ऐसा ढांचा अपनाया है जहां उन्हें कानून बनाने के लिए सार्वजनिक मशविरा करना ही पड़ता है।

अच्छी मंशा के बाद भी ऐसा ज्यादा होता नहीं दिखता। कई प्राथमिक और उप विधान सार्वजनिक चर्चा के बगैर बनाए जा रहे हैं। जब निर्वाचन के बगैर बने नियामक आम मशविरे के बगैर कायदे बनाने लगते हैं तो चिंता बढ़ जाती है। मशविरा किया जाता है तब भी कुछ अपवादों को छोड़कर उनकी सार्थक भागीदारी, आर्थिक विश्लेषण आदि नहीं होने दिया जाता।

तब से अब तक सार्वजनिक मशविरे की कला और विज्ञान बदल गए हैं। जनता तक पहुंचने के लिए अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन चर्चा और आपसी संवाद जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। सलाहकार समिति, कार्य समूह, राउंडटेबल, सेमिनार, कार्यशाला या परिचर्चा पत्र जैसे उपाय आजमाए जाते हैं। नागरिक समाज के बनाए मंच भी हैं, जहां से जनता को किसी भी मसौदे पर अपने सुझाव सार्वजनिक तौर पर देने का मौका मिल जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नियम निर्माण में हितधारकों को शामिल करने के लिए ओईसीडी की निर्देशक नियामक प्रक्रिया में सारे तरीके बताए गए हैं। यूएनडीपी का सार्वजनिक परामर्श सूचकांक देखता है कि सार्वजनिक मशविरे के प्रयास कितने अच्छे और कारगर रहे।

मशविरे की मजबूत प्रक्रिया में स्पष्टता, समावेशन, और जवाबदेही कारगर रहनी चाहिए। सबसे पहले सार्थक भागीदारी की शुरुआत मशविरे के लिए व्यवस्थित सामग्री प्रदान करने से होती है, जिससे भागीदारों को जरूरी संदर्भ, कानून की जरूरत, अनुभव के आधार पर आकलन, आर्थिक विश्लेषण और नियम-नीतियों का मसौदा मिलना चाहिए। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर मशविरे के दौरान ऐसा ही किया गया। एक पोर्टल बनाया गया जहां नागरिक जरूरी सरकारी रिपोर्ट और दस्तावेज देख सकते थे। इससे वे अतीत के घटनाक्रम और नीति का नजरिया समझकर बेहतर प्रतिक्रिया दे पाते हैं।

दूसरा, मशविरा कामयाब तभी होता है, जब उसमें सही लोगों की भागीदारी हो। कानून बनाने वाले इसके लिए औपचारिक सूचना, डिजिटल मंच सीधे संपर्क जैसे कई तरीके अपनाते हैं। दिव्यांगों से संबंधित नई राष्ट्रीय नीति पर सामाजिक न्याय मंत्रालय का मशविरा एक उदाहरण है। इसमें ब्रेल तथा भारतीय संकेत भाषा का प्रयोग किया गया ताकि दिव्यांग आराम से उसमें भागीदारी कर सकें। पूरी नीति का अनुवाद करके मंत्रालय तथा राज्य सरकारों की वेबसाइटों के जरिये बांटा भी गया।

तीसरा, पारदर्शिता से प्रक्रिया की विश्वसनीयता और भरोसा बढ़ते हैं। भागीदारों के सुझावों और उन सुझावों पर विभागों या नियामकों की चर्चा का संक्षिप्त ब्योरा एवं प्रतिक्रिया प्रकाशित करना सबसे अच्छा रहता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पास केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल है, जहां सभी टिप्पणियां और उनके जवाब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

चौथा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं स्वतंत्र निगरानी की हिमायत करती हैं ताकि मशविरा प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके। मगर विधि निर्माण संस्थाएं क्रियान्वयन को प्राथमिकता देती हैं। इससे व्यवस्थित आकलन की गुंजाइश कम रह जाती है। इसे हल करने के लिए सार्वजनिक मशविरा प्रक्रिया के मानक बनाना जरूरी है। कानून बनाने वालों को कहा जाना चाहिए कि वे मशविरे के व्यवस्थित तरीके अपनाएं और मानक सूचकांक के जरिये गुणवत्ता तथा प्रभाव को सामने लाएं।

आखिर में, शासन की बढ़ती जटिलताओं के बीच सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलता दिख रहा है। अधिकारी माईगॉव जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से विचार जुटा रहे हैं। ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड जैसे नियामक हितधारकों को किसी भी समय नए नियम सुझाने या संशोधन सुझाने का अवसर देते हैं। यह तरीका सभी मंत्रालयों और नियामकीय संस्थाओं में अपनाए जाने की जरूरत है। इससे जनता को साल भर कानूनों पर सुझाव देने का मौका मिलेगा और सरकारी एजेंसियों को उन पर विचार करने का अवसर मिलेगा। इससे भागीदारी भी बढ़ेगी और कानून भी बेहतर होंगे।

इन तरीकों को संहिताबद्ध करने से पक्का हो जाएगा कि कानून निर्माता उन्हीं मानकों और जवाबदेही का पालन करें, जिनकी वे हितधारकों से अपेक्षा करते हैं। सार्वजनिक मशविरा नहीं करने पर जिम्मेदार लोगों पर जुर्माना लगना चाहिए और वह कानून निरस्त कर दिया जाना चाहिए। साथ ही क्षमता निर्माण और प्रोत्साहन ढांचा तैयार करने की कोशिश होनी चाहिए ताकि सार्वजनिक मशविरे के लिए उचित माहौल बन सके।

तकनीक पर कब्जे के दौर में संसाधनों की साझेदारी

स्पेन के बार्सिलोना शहर में हर साल होने वाला दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इस बार कुछ खास रहा क्योंकि डॉनल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दूरसंचार उद्योग के दिग्गज पहली बार एक साथ इकट्ठे हुए। इनमें टेलिफोनिका और चाइना मोबाइल से टेलस्ट्रा, टेलिनॉर और भारती एयरटेल तक के मुखिया शामिल थे। सम्मेलन की दिशा पहले ही दिन टेलिफोनिका के चेयरमैन एवं सीईओ मार्क मर्टरा के भाषण ने तय कर दी। उन्होंने अधिक से अधिक फायदे के लिए तकनीक और दूरसंचार के संबंध को प्रगाढ़ बनाए जाने पर जोर दिया। मध्यकालीन गलियों, खूबसूरत वास्तुकला और बार्का (फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना) के लिए मशहूर इस शहर से मर्टरा का वीडियो पूरी दुनिया में देखा गया, जिसमें उन्होंने कहा, 'वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और न ही तकनीक।'

जब भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल मंच पर पहुंचे तो उन्होंने एक साथ आने और साझा करने की जरूरत पर पूरा जोर दिया। उन्होंने उद्योग, नियामकों और दुनिया भर की सरकारों से इसे सुनने और समझने की गुजारिश की। दूरसंचार कंपनियों और उनके साथ साझेदारी करने वाली तकनीकी कंपनियों के लिए मित्तल का एक ही संदेश था: साझा कीजिए और साझा कीजिए। इसका मकसद तकनीकी ढांचे को एक-दूसरे के साथ साझा कर लागत घटाना और मुनाफा बढ़ाना है। दूरसंचार की बड़ी हस्तियां वक्त के साथ चल रही हैं और जानती हैं कि तकनीक में (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से 5जी प्लस तक) भारी निवेश अब टाला नहीं जा सकता। उनका जोर इस बात पर है कि अकेले न चलकर बुनियादी ढांचा सबके साथ बांटा जाए तो चुनौती भरे इस माहौल में निवेश का बोझ बहुत कम हो सकता है।

सामयिक सवाल

निवेदिता मुखर्जी

विश्व व्यवस्था पर अपना दबदबा बढ़ाने की ट्रंप की मंशा को देखते हुए हर देश समझ रहा है कि आर्थिक बदलाव होना ही है और इस बदलाव में तकनीक की बहुत अहमियत है। कोविड-19 में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला इस कदर बरबाद हो गई थी कि उसके उबरने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसी दौर की तरह एक बार फिर देश अपने ही भरोसे रह गए हैं। ऐसे में तकनीकी संप्रभुता या तकनीक पर पूरी तरह नियंत्रण करने की बात उठने लगी है। इस समाचार पत्र द्वारा पिछले दिनों आयोजित एक कार्यक्रम में एचसीएल के सह-संस्थापक अजय चौधरी ने यही बात कही थी। विश्व व्यवस्था इतनी अप्रत्याशित हो गई है कि अपनी तकनीक, डेटा तथा डिजिटल ढांचे पर नियंत्रण रखने की किसी देश की क्षमता (तकनीकी संप्रभुता) को 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में अहम कदम माना रहा है।

करीब 25 साल से बार्सिलोना सम्मेलन में और उससे पहले दुनिया भर में हुई जीएसएम वर्ल्ड कांग्रेस में लगातार पहुंचने वाले मित्तल ने भी तकनीकी संप्रभुता की बात उठाई मगर उनका तरीका कुछ अलग था। मंच से जब उन्होंने तकनीक साझा करने का आह्वान किया तो उनका साफ मतलब था कि तकनीक में उत्कृष्टता और नया स्तर हासिल करने के लिए एक-दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि ब्रांड और सेवा में होड़ होनी चाहिए अपना अलग पूंजीगत ढांचा बनाने में नहीं। क्या तकनीक पर नियंत्रण की मौजूदा होड़ में उनकी बात सुनी जाएगी?

सम्मेलन में उपग्रह संचार (सैटेलाइट कम्युनिकेशन या सैटकॉम) का भी सरसरी तौर पर जिक्र किया गया। भारत में उपग्रह संचार की स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण इसका स्पेक्ट्रम सालों से अटका पड़ा है। इसमें भी जोर तकनीक एवं संसाधन साझा करने पर ही था। मित्तल ने टेस्ला के संस्थापक एवं ट्रंप के करीबी सहयोगी ईलॉन मस्क का नाम लिए बिना सैटकॉम में स्पेक्ट्रम आवंटन पर टकराव का जिक्र किया। मस्क के नियंत्रण वाली कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटकॉम में उतरना चाहती है और उसने नीलामी के बगैर सीधे स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाने की मांग की है। मगर दूरसंचार उद्योग जगत के ज्यादातर लोगों ने नीलामी से स्पेक्ट्रम आवंटन के पक्ष में हैं। सरकार ने भी कह दिया है कि दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी स्पेक्ट्रम नीलामी के बगैर दिया जाएगा मगर अभी यह नहीं पता कि कीमत कितनी रहेगी।

मित्तल ने बार्सिलोना सम्मेलन में मस्क की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह लड़ाई का वक्त नहीं है। सुदूर इलाकों और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अहमियत समझाते हुए उन्होंने कहा कि बचे हुए 40 करोड़ लोगों को दूरसंचार के दायरे में लेने का काम पूरा करना ही होगा।

दुनिया के इस सबसे बड़े दूरसंचार सम्मेलन में एकीकरण, ढांचे की साझेदारी और निवेश पर बेहतर रिटर्न की बातें जोर-शोर से उठाई गईं मगर चीन से आई एक बड़ी शख्सियत के विचार सबसे अलग रहे। चाइना मोबाइल के प्रेसिडेंट और सीईओ हे प्याओ ने एक ऐसी बात कही, जिस पर शायद ही किसी ने ध्यान नहीं दिया हो। उनकी बात का अंग्रेजी अनुवाद जब हॉल में गूंजा तब लोगों ने सुना, 'ए आई प्लस को हम बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और बदल डालते हैं..'।

हे का मतलब था कि ए आई प्लस की दशा-दिशा चीन ही तय करता है और उनके भाषण में कुछ भी साझा करने की बात नहीं कही गई थी। जाहिर है कि चीन की सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी (जिस पर पीपल्स रिपब्लिक) को संसाधन साझा करने की कोई जरूरत नहीं लग रही है। यह उन दूरसंचार कंपनियों के रुख से एकदम उलट रहा, जो बार्सिलोना के मंच से अपनी सरकारों और नियामकों को कर तथा शुल्क कम करने के लिए कह रही थीं। तकनीक पर पूरी तरह कब्जा करने की हसरतों के इस दौर में क्या उनकी बात सुनी जाएगी?

आपका पक्ष

ट्रंप की नीतियों के कारण वैश्विक हलचल

लेख 'ट्रंप के कदम और मंदी का जोखिम' में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण वैश्विक मंदी का आना लाजिमी लगता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा, उनका चुनावी नारा) के वादे को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित निर्णय लिए हैं। अमेरिकी में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए मेक्सिको सीमा पर दीवार खड़ी करने जैसे निर्णय लिए गए। व्यापार शुल्क पर ट्रंप का सख्त रुख दूसरे देशों के साथ ही अमेरिका को भी चिंता में डालने लगा है। ट्रंप कई देशों में व्यापार शुल्क बढ़ाने की घोषणा कर चुका है और कुछ देशों में व्यापार शुल्क बढ़ा दिया गया है। इससे उन देशों के साथ व्यापार पर खासा असर पड़ने लगा है। ट्रंप के इस कार्रवाई के जवाब में कई देश एकजुट होने लगे हैं तथा वे अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर भी शुल्क बढ़ाने की बात कही है लेकिन अभी तक यह बढ़ाया नहीं गया है। ट्रंप के इसी निर्णय के कारण मंदी का खतरा मंडराने लगा है। मंदी की संभावना का पैमाना न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के पास है जिसका अनुमान है कि मंदी सूचकांक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है जिससे अब मंदी का खतरा सिर पर मंडराने लगा है। मंदी का असर पूरे विश्व पर नकारात्मक असर पड़ता है। विश्व की शक्तिशाली देश अमेरिका को अपने कुछ फायदे साधने के लिए पूरे विश्व को मंदी की आग में धकेल देना ठीक नहीं है। अमेरिका विकासशील तथा गरीब देशों को विकास में सहयोग के लिए दान देता है जो ट्रंप प्रशासन ने ऐसे 80 फीसदी दान कार्यक्रमों को बंद कर दिया है। इसका व्यापक वैश्विक असर पड़ेगा तथा छोटे देश इससे ज्यादा प्रभावित होंगे।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डॉनल्ड ट्रंप ने व्यापार शुल्क में बढ़ोतरी करने की घोषणा की

ई-वाहन सस्ते हों, सार्वजनिक परिवहन में इस्तेमाल बढ़े

सरकार ई-वाहनों पर जीएसटी दरों को घटा सकती है ताकि इनकी कीमत पारम्परिक वाहनों के मुकाबले सस्ती हो। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाना और उन्हें सुवि-धाजनक स्थानों पर स्थापित किया जाए। ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सकें। सरकार को सार्वजनिक परिवहन, जैसे बसों और टैक्सियों में ई-वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। बैटरी तकनीक और रेंज में सुधार। ताकि ईवी की बैटरी की लाइफ लंबी हो और एक बार चार्ज करने पर अधिक दूरी तय की जा सके।

अंकित सोनी, मनावर

ई-वाहनों को किफायती और सुरक्षित बनाना होगा

ई-वाहनों के प्रति लोगों का रुझान लाने के लिए उनका सुविधायुक्त व सुरक्षित होना जरूरी है। इसके लिए ई-वाहन निर्माताओं को वे ध्यान रखना होगा कि ये वाहन परं-परागत ईंधन वाहनों से क्षमता में किसी प्रकार कम न हों। साथ ही देश में ई—मोबिलिटी के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर होने से स्वतः ई-वाहनों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। इन वाहनों का किफायती होना तो जरूरी है ही पर उनका उपयोग और संरक्षण भी आसान और कम खर्चीला होना भी आवश्यक है।

प्रयाग उदेनिया, दमोह

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां भी मौजूद थे।

कल्पमेधा

मानव जाति युग-युगांतर से उन स्वार्थी लोगों द्वारा अज्ञान में कैद रखी गई है, जिनका लक्ष्य मनुष्य के दिमागों को संकुचित और अव्यवस्थित बनाए रखना रहा है।

- आर. जैफरिन

संशय का प्रवाह

प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र के पानी में प्रदूषण का तथ्य उजागर कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने खासा विवाद पैदा कर दिया था। पर, अब अपनी नई रपट में उसने स्पष्ट किया है कि वहां का पानी स्नान करने लायक था। चूंकि अलग-अलग जगहों से जल के नमूने लिए गए थे, इसलिए उनमें अलग-अलग तथ्य दर्ज हुए थे, मगर इससे पूरी नदी के पानी में अपशिष्ट की मात्रा का दावा नहीं किया जा सकता। रपट में कहा गया है कि, सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार, जांचे गए खंडों के लिए पीएच, डीओ, बीओडी और एफसी का औसत परिमाण संबंधित मानदंडों/ अनुमेय सीमाओं के भीतर है। यह रपट 12 जनवरी से 22 फरवरी के बीच इकट्ठा किए गए आंकड़ों का समग्र विश्लेषण करने के बाद पेश की गई है। इसी अवधि में सभी प्रमुख स्नान हुए थे। सीपीसीबी ने 17 फरवरी को पेश अपनी रपट में बताया था कि संगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर फीकल कोलीफार्म का स्तर स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता के अनुरूप नहीं था। इस रपट के आधार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया था। तब राज्य सरकार को सफाई देनी पड़ी थी कि उसने गंगा और यमुना के जलशोधन के लिए क्या-क्या उपाय किए हैं और वहां पानी पूरी तरह स्नान के लायक है। बाद में एक वैज्ञानिक ने भी कहा कि पूरे महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र का पानी पीने लायक था।

इस बार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को इसलिए विशेष माना गया था कि इसे एक सौ चौवालीस वर्ष बाद आया अवसर बताया गया। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके आयोजन का बढ़-चढ़ कर प्रचार-प्रसार किया था। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हर व्यवस्था करने की कोशिश की गई थी। संगम क्षेत्र में पहुंचने वाले गंगा और यमुना के जल को हर दिन जांचने का प्रबंध भी किया गया था, ताकि उसमें किसी तरह की ऐसी अशुद्धि न घुल सके, जिससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचता हो। ऐसे में जब सीपीसीबी ने संगम क्षेत्र के पानी में फीकल कोलीफार्म यानी मानव जल-मल से पैदा बैक्टीरिया की मात्रा मानक से अधिक होने का तथ्य उजागर किया, तो लोगों की आस्था पर चोट का प्रश्न उठ खड़ा हुआ था। दरअसल, महाकुंभ के दौरान लोग आचमन भी करते हैं, वहां का पानी भर कर अपने घर लाते हैं। इस बैक्टीरिया से लोगों में गंभीर त्वचा रोग और दूसरी बीमारियां पनपने की आशंका पैदा हो गई थी।

यह समझना मुश्किल है कि अब सीपीसीबी को अपने पिछले अध्ययन को दुरुस्त करने का कौन-सा सूत्र हाथ लगा है, जो उस वक्त उसके पास नहीं था। गनीमत है कि उसकी पहली रपट का श्रद्धालुओं पर कोई व्यापक और गंभीर असर नहीं पड़ा था, वरना इससे बेवजह विवाद के तूल पकड़ने का खतरा तो पैदा हो ही गया था। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी मानी जाए, कि एक रपट के जरिए पहले संशय पैदा करने की कोशिश की गई, फिर महाकुंभ खत्म हो जाने के बाद उसे दुरुस्त कर दिया गया। हालांकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अभी इस प्रकरण को बंद नहीं किया है। इस पर सुनवाई होनी है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि इस संशय का निवारण किया जाएगा कि आखिर सीपीसीबी की कौन-सी रपट सही है, पहले वाली या बाद की।

जश्न बनाम हिंसा

भारत के आइसीसी चैंपियंस ट्राफी जीतने पर देश में सभी को खुशी हुई होगी। इस मौके पर जश्न मनाना भी स्वाभाविक है। मगर इससे उपजी इस अफसोसनाक स्थिति पर समाज के सभी संवेदनशील लोगों को सोचने की जरूरत है कि अगर कोई मौका सभी के लिए खुश होने का हो, उस समय दो पक्षों के बीच टकराव देश को किस ओर ले जाएगा। गौरतलब है कि चैंपियंस ट्राफी में भारत के खिताब जीतने के बाद जब रविवार को मध्यप्रदेश में इंदौर के महू में कुछ लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे, तो एक मस्जिद के पास दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद पत्थरबाजी हुई और फिर लोगों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। गुजरात के गांधीनगर में भी जीत के जश्न में निकाली गई रैली के दौरान हिंसक घटना हुई। हालांकि पुलिस ने स्थिति संभाल ली, मगर यह सवाल बेहद दुखद है कि खुशी जाहिर करने के मौके पर किसी भी व्यक्ति या समूह को तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने की खुराफात क्यों सूझती है और क्या ऐसे लोग समाज और देश के हित को प्रभावित नहीं करते।

दरअसल, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, तब सबसे ज्यादा देश की उस सांस्कृतिक संरचना को नुकसान पहुंचता है, जिसमें आमतौर पर सभी लोग शांति और खुशी से साथ रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, जिनमें देश की किसी उपलब्धि पर खुशी जाहिर करने के क्रम में दो पक्षों के बीच टकराव और हिंसा की स्थिति बन जाती है। यह बेहद तकलीफदेह स्थिति है। इसके बाद भले पुलिस दखल देकर स्थिति पर नियंत्रण कर ले, मगर इस बीच आपसी संदेह का जो माहौल बन जाता है, वह किसी के लिए अच्छा नहीं होता। आमतौर पर लोगों को बेवजह उन्माद से नुकसान समझ में आ जाता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है और बहुत कुछ बिगड़ जाता है। जरूरत इस बात की है कि खुशी और जश्न के बीच होने वाली हिंसा की घटनाओं को सबक के तौर पर लिया जाए और सभी समुदाय के लोग इस मसले पर सजग रहें, ताकि वैसी स्थिति दोबारा न पैदा हो।

पढ़ाई में अव्वल, हुनर में पिछड़ते युवा

कुछ अध्ययन यह साबित कर रहे हैं कि हमारे नौजवान हुनर या दक्षता के मामले में वह धार खो चुके हैं जो उन्हें किसी नौकरी या रोजगार के काबिल बनाती है। इधर इसकी पुष्टि मर्सर-मेटल की रपट ने की है कि विश्वविद्यालयों से निकले केवल 42.6 फीसद भारतीय स्नातक रोजगार योग्य हैं।

अभिषेक कुमार सिंह

देश में अरसे से यह आह्वान किया जाता रहा है कि शिक्षा रोजगारपरक होनी चाहिए। यह मिथक अब टूट चुका है कि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ ज्ञानार्जन होता है। आज हमारे देश में विद्यार्थी बेहद महंगी हो चुकी पढ़ाई इसलिए करते हैं, ताकि उन्हें कोई रोजगार, खासकर नौकरी मिल सके। ऐसे दौर में, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) के आगमन के साथ रोजगार संकट गहराता लग रहा है, कुछ अध्ययन यह साबित कर रहे हैं कि हमारे नौजवान हुनर या दक्षता के मामले में वह धार खो चुके हैं, जो उन्हें किसी नौकरी या रोजगार के काबिल बनाती है। इसकी पुष्टि मर्सर-मेटल की रपट से भी हुई है कि विश्वविद्यालयों से निकले केवल 42.6 फीसद भारतीय स्नातक रोजगार योग्य हैं। इनमें गैर-तकनीकी दक्षता से लेकर रचनात्मक श्रेणी के रोजगार शामिल हैं।

देश के सत्ताइस सौ से अधिक विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के परिसरों में मौजूद दस लाख से ज्यादा छात्रों के बीच जुटाए गए आंकड़ों से तैयार की गई मर्सर-मेटल की रपट इस मामले में पिछले वर्षों के मुकाबले गिरावट दर्शा रही है। वर्ष 2024 में देश के 42.6 फीसद भारतीय स्नातक रोजगार योग्य पाए गए, जो 2023 के 44.3 फीसद के मुकाबले एक फीसद कम हैं। रपट के मुताबिक इस गिरावट की मुख्य वजह तकनीकी कौशल की कमी है। कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी नौकरियों में युवा रोजगार लायक हुनर हासिल कर रहे हैं, जबकि मानविकी-कला आदि संकायों में उनकी दक्षता में गिरावट आ रही है। अगर राज्यवार बात की जाए तो मर्सर-मेटल की रपट कहती कि भारत के स्नातक कौशल सूचकांक 2025 में दिल्ली के युवा 53.4 फीसद के साथ रोजगार क्षमता में सबसे ऊपर हैं।

करीब छह वर्ष पहले एक एजंसी 'एस्पाइरिंग माइंड' की रपट में भी ऐसे ही खुलासे किए गए थे। इसमें कहा गया था कि हमारे देश में इंजीनियरिंग कर चुके 80 फीसद छात्र नौकरी के काबिल नहीं हैं, क्योंकि उनमें नौकरी की जरूरत के मुताबिक कौशल की काफी कमी होती है। यह रपट 650 से ज्यादा इंजीनियरिंग कालेजों के उन डेढ़ लाख इंजीनियरिंग स्नातकों पर आधारित थी, जिन्होंने करीब दस साल पहले 2015 में डिग्री हासिल की थी। इस रपट के दावों की पुष्टि नेशनल सैंपल सर्वे आफिस (एनएसएसओ) के सर्वेक्षण से भी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि देश के स्नातक दस युवाओं में से महज एक युवा ऐसा प्रशिक्षण यानी 'वोकेशनल ट्रेनिंग' हासिल करता है, जिसके बल पर उसे नौकरी दी जा सके। ऐसे दौर में, जब देश में 'स्किल इंडिया' जैसे महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम में देश के करोड़ों युवाओं को हुनरमंद बना कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, समय-समय पर आने वाले सर्वेक्षणों और रपटों के तथ्य तथा आंकड़े हमें हैरान करते हैं।

ऐसे में यह अहम सवाल है कि आखिर कैसे हमारा देश अपने युवाओं में वह दक्षता पैदा कर पाएगा, जिसके बल पर वे कोई अच्छी नौकरी पाने या कोई कारोबार खड़ा करने की स्थिति में आ सकता है। हालांकि इस मामले से जुड़ा एक गंभीर पहलू यह भी है कि हमारे देश में सरकारों के पास फिलहाल 35-50 लाख युवाओं को ही हर साल किसी एक क्षेत्र में दक्ष बनाने वाले प्रशिक्षण का प्रबंध है। इसकी तुलना पड़ोसी चीन से करें, तो पता चलता है कि वहां सालाना नौ करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है।

> **आज सबसे अहम बात यह है कि युवाओं की रोजगार क्षमता मांग के हिसाब से होनी चाहिए। यानी वे ऐसे हुनर से लैस हों, जिसकी उद्योग को जरूरत है और जिसे नवीनतम तकनीक के अनुसार ढाला जा सके। यह बात चीन, जापान, कोरिया और जर्मनी जैसे देशों ने सीखी है। लिहाजा वहां का अधिकतर मानव संसाधन दक्ष है और यही उनकी सफलता का राज है। असल में, दक्ष लोगों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास होता है। वे एक चीज को सीखने के बाद दूसरी नई चीज सीखना चाहते हैं और यही ललक उन्हें दूसरों से अलग करती है। इस पैमाने पर भारत को देखें, तो यहां के शहरों में ही इस नएपन की थोड़ी-बहुत झलक मिलती है।**

इस समस्या का दूसरा पहलू और गंभीर है। यह पहलू शिक्षण-प्रशिक्षण की गुणवत्ता से जुड़ा है। यह देखा जा रहा है कि अगर युवा किसी तरह नामी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला पा जाते हैं, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहां से जो डिग्री या डिप्लोमा लेकर निकलेंगे, उसके बल पर वे इतने काबिल हो सकेंगे कि अपने क्षेत्र में हर चुनौती का मुकाबला कर सकें। यह मामला स्कूल, कालेजों और प्रतिष्ठानों में दी जा रही शिक्षा की खराब गुणवत्ता का है। कुछ ही वर्ष पहले पीयर्सन नामक कंपनी ने देश के 527 शहरों के उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों और स्कूलों के बीच एक सर्वेक्षण किया था। इसमें कहा गया था कि देश की राजधानी दिल्ली तक में शिक्षक इसका खयाल नहीं रखते कि शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मुहैया करा पा रही है या नहीं। यही कारण है कि देश में लाखों युवा पढ़-लिखे होने के बावजूद खुद को किसी ठीक-ठाक नौकरी के लिए तैयार नहीं कर पाए या उसमें अपनी योग्यता नहीं दिखा पाए। जाहिर है, इसमें एक बड़ी समस्या मौजूदा शिक्षा-तंत्र की है, जो छात्रों को वैसी शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं दे पा रहा है, जो अच्छी नौकरी पाने या अपना कोई व्यवसाय खड़ा करने में उनकी मदद करे।

आज सबसे अहम बात यह है कि युवाओं की रोजगार क्षमता मांग के हिसाब से होनी चाहिए। यानी वे ऐसे हुनर से लैस हों, जिसकी उद्योग को जरूरत है और जिसे नवीनतम तकनीक के अनुसार ढाला जा सके। यह बात चीन, जापान, कोरिया और जर्मनी जैसे देशों ने सीखी है। लिहाजा, वहां का अधिकतर मानव संसाधन दक्ष है और यही उनकी सफलता का राज है। असल में, दक्ष लोगों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास होता है। वे एक चीज को सीखने के बाद दूसरी नई चीज सीखना चाहते हैं और यही ललक उन्हें दूसरों से अलग करती है। इस पैमाने पर भारत को देखें, तो यहां के शहरों में ही इस नएपन की थोड़ी-बहुत झलक मिलती है। शहरों के युवा अच्छे जीवन की चाह में नए कौशल सीखते हैं और नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करते हैं। जैसे, इधर एआइ से जुड़ी डिग्री लेने का चलन शहरों में बढ़ा है। लेकिन देश के गांव-कस्बों में ऐसी इच्छा का घोर अभाव है।

गांव-कस्बों और छोटे शहरों में बेरोजगारी की समस्या इसीलिए तेजी से विकराल होती जा रही है। यदि वहां के युवा शहर जाकर कोई तकनीकी डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो गांव-कस्बों में लौटने के बाद वे वहां अपने हुनर की आजमा नहीं पाते हैं। इस कारण उनके व्यावहारिक अनुभव में कमी रह जाती है, जिससे नौकरी की होड़ में वे पिछड़ जाते हैं। इसका परिणाम देश में हुनरमंद लोगों की कमी के रूप में सामने आता है। यदि लोगों के पास कोई कौशल हो, लेकिन वह उद्योग की मांग के मुताबिक न हो, तो हुनर और बाजार के बीच तालमेल नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में दक्षता होने के बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। निश्चय ही ऐसे निष्कर्ष चिंताजनक हैं और सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर वह अपनी युवा आबादी को किस तरह की शिक्षा मुहैया करा रही है। सर्वेक्षणों के नतीजे हमें यह सोचने को भी मजबूर करते हैं कि आखिर हम युवा पीढ़ी को उनके सपने साकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं कर पा रहे हैं।

भूलते भागते क्षण

सतीश खनगवाल

एक छोटे से पार्क में दस-बारह साल के पांच-सात बच्चे खेल रहे थे। आज के समय में जब हर समय मोबाइल में घुसा हुआ है, ऐसे समय में इन बच्चों को पार्क में खेलते देखना कई लोगों के लिए एक सुखद आश्चर्य था। आधुनिक जीवनशैली में घुले और रच-बस गए लोग सोच सकते हैं कि इसमें सुखद आश्चर्य वाली कौन-सी बात है! बच्चे तो पार्क में खेलते ही हैं। मगर सुखद आश्चर्य इस बात का था कि बच्चे एक पेड़ के नीचे कांच की गोलियों से खेल रहे थे। यह खेल एक प्रकार से हमारा देसी खेल है। आमतौर पर उत्तर भारत के गांव-कस्बों में नवंबर से मार्च तक और अन्य महीनों के दौरान भी सुविधानुसार बच्चे बड़े चाव से कांच की गोलियां खेलते हैं। बच्चों की इस प्रकार खेलता देख हमें सभी से कइयों को अपना बचपन याद आना स्वाभाविक ही है और जब बचपन याद आए तो बचपन के खेल भी याद आएंगे।

कांच की गोलियों के साथ-साथ 'सितौलिया' या 'पिट्ठू' बहुत सारे वैसे बच्चों का प्रिय खेल होता था, जो आज बड़े हो गए हैं और आधुनिक वीडियो गेम को ही खेल मानते होंगे। यह एक ऐसा खेल है जो भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से खेला जाता है। सात पत्थरों को बड़ी मेहनत से तराश कर गोल पिट्ठू बनाए जाते। फिर कपड़े की एक गेंद तैयार कर पांच-सात मित्रों के साथ खेला जाता। एक के ऊपर एक पिट्ठू जमा कर गेंद से पिट्ठू गिराई जाती। दिमाग और शारीरिक चपलता का अद्भुत मिश्रण था यह खेल। उस समय के लोग 'छुपम छुपाई' या 'आइस-पाइस' को कैसे भूल सकते है? दिन में तो खेलते ही थे, लेकिन अक्सर संध्या के मद्धिम अंधेरे में इस खेल का आनंद अलग ही होता था। जब सारे मित्र निर्धारित क्षेत्र में छिप जाते और कोई एक उन्हें ढूंढ़ता। साथियों को ढूंढ़ने और 'धप्पा' करने में जो आनंद और सुख की अनुभूति होती थी, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह तो बस खेलने वाला ही जान सकता है।

एक खेल में एक साथी अपने एक पैर को उठाकर एक पैर से चलकर या दौड़कर अपने साथियों में से किसी एक को पकड़ने की कोशिश करता था। बाकी साथी दांए-बांए होकर, दौड़कर न केवल अपने आपको बचाते, बल्कि पकड़ने वाले बच्चे को छेड़ते। उसके सिर पर या पीठ पर हल्की-फुल्की चपत लगाते। 'धरणी डंकण', जिसमें एक पेड़ के नीचे गोला बनाकर एक छोटे से डंडे को पैर के नीचे से फेंका जाता था। एक साथी जब तक डंडा उठाकर लाता, तब तक बाकी साथी पेड़ पर चढ़ जाते। डंडा उठाकर लाने वाला डंडे को गोले में रखकर पेड़ पर चढ़कर किसी साथी को पकड़ने या छूने की कोशिश करता। बाकी बच्चे पेड़ से कूदकर डंडा उठाकर फिर फेंकने की कोशिश करते। बड़ा ही मजेदार खेल था।

इनके अतिरिक्त पोसम पा, हरा समंदर गोपीचंदर, घोड़ा जमाल खाई, पकड़म पकड़ाई, गुल्ली-डंडा, गुट्टे, भर-घर, स्टापू या पहलक-दुहलक, काफी में क्वास-जीरो, खाने बनाना, अंत्याक्षरी आदि कितने ही ऐसे खेल थे जो हमारी दिनचर्या के अनिवार्य अंग थे। अंत्याक्षरी कभी गीतों की, तो कभी दोहों-पदों की, कभी अंग्रेजी की वर्तनी की तो कभी गांव, शहर और देश के नामों की होती। अच्छी बात यह थी कि ये सारे ऐसे खेल थे, जिनमें लड़के-लड़कियों के बीच भेदभाव नहीं था। सभी मिलकर ये खेल खेलते।

उन खेलों की विशेषता यह थी कि इनसे शरीर के साथ-साथ दिमागी कसरत भी खूब होती। सामान्य ज्ञान भी खूब बढ़ता। इनके अतिरिक्त खो-खो, कबड्डी, फुटबाल, क्रिकेट आदि भी साथ-साथ चलता रहता। फिर क्रिकेट की ऐसी आंधी आई जिसमें सभी खेल लगभग उड़ते दिखाई दिए। रही-सही कसर टीवी और वीडियो गेम ने पूरी कर दी। आगे चलकर इंटरनेट और मोबाइल ने सब कुछ को ग्रास लिया। हम लाख दावा करें हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार का, लेकिन पिछले पंद्रह से बीस सालों में पढ़ाई-लिखाई का जबरदस्त तनाव और दबाव भी बच्चे झेल रहे हैं और यह कम होने के स्थान पर बढ़ ही रहा है। अगर आज की बात करें तो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल और पढ़ाई-लिखाई के दबाव ने मिलकर बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है।

दुनिया मेरे आगे

> **फिर क्रिकेट की ऐसी आंधी आई जिसमें सभी खेल लगभग उड़ते दिखाई दिए। रही-सही कसर टीवी और वीडियो गेम ने पूरी कर दी। आगे चलकर इंटरनेट और मोबाइल ने सब कुछ को ग्रास लिया। हम लाख दावा करें हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार का, लेकिन पिछले पंद्रह से बीस सालों में पढ़ाई-लिखाई का जबरदस्त तनाव और दबाव भी बच्चे झेल रहे हैं।**

आज जिसे भी देखा जाए, चाहे वह बच्चा हो, युवा हो, अधेड़, बुजुर्ग, सभी मोबाइल के अंदर झांकने में लगे हैं। बच्चे तो इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। उचित शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बचपन सबसे प्रभावी उम्र होती है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ऐसे में खेल बच्चों के लिए बेहद अनिवार्य है। पर आज का बच्चा शिक्षा का दबाव झेल रहा है। आज का समय ऐसा हो गया है कि माता-पिता दोनों को कमाने के लिए निकलना पड़ता है। थके-हारे जब लौट कर आते हैं तो बच्चे परेशान न करें, इस डर से वे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल में तरह-तरह के रील, गेम और अश्लील सामग्री देखकर बच्चा भटक जाता है। यह हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। अपने ही परिवार, पड़ोसी, मित्रों से कटने लगता है। उसमें सामाजिकता और संवेदनशीलता कम होती जाती है। ये देखकर तो और बुरा लगता है जब गली-मुहल्ले के बच्चे आपस में एक-दूसरे को नहीं जानते या कम जानते हैं।

जबकि खेलों से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। उनमें स्वस्थ प्रतियोगिता, सहयोग, सामाजिकता, सहायता, मित्रता आदि की भावना पनपती है। बच्चे जीत और हार, दोनों के लिए एक जैसे तैयार रहते हैं। उनमें खेल भावना विकसित होती है। इसलिए बच्चों पर से पढ़ाई-लिखाई का दबाव कम करना चाहिए। जितना हो सके उन्हें मोबाइल से दूर रखना चाहिए और उन्हें शारीरिक खेलों के लिए प्रेरित करना चाहिए।

निरर्थक विवाद

भारत एक विशाल देश है। यहां अलग-अलग धर्मों-जातियों के लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य का अपना पहनावा अपनी संस्कृति और अपनी भाषा है। यहां कुछ कोस के बाद ही पानी का स्वाद और बोली बदल जाती है। यहां तक की अलग-अलग राज्यों में भी कई तरह की भाषा बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी छोर की भाषा अलग है तो बिहार में आरा, सीवान, समस्तीपुर और दरभंगा की भाषा अलग। दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है। संख्या के हिसाब से हिंदी इस देश में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। देश के लगभग सभी लोग हिंदी भाषा को समझते हैं। हिंदी फिल्में भी पूरे देश में देखी जाती हैं। आम आदमी किसी भी भाषा का विरोध नहीं करता, लेकिन एक दो राज्यों में हिंदी को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं। हम 140 करोड़ लोग अलग-अलग धर्म और अलग-अलग जातियों, प्रांतों तथा भाषाओं के नाम पर बंटे हुए हैं। फिर भी हम एक हैं। हमें यह समझना होगा की भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं।

- धरनजीत अरोड़ा, नरेला, दिल्ली

अनुशासन का प्रतिफल

भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता मेहनत, संघर्ष और त्याग का प्रतीक है। यह टीम लगातार कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए विश्व क्रिकेट में अपनी जगह बनाती रही है। मेहनत का उदाहरण सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों में देखा जा सकता है। ये खिलाड़ी वर्षों तक कठिन अभ्यास और अनुशासन के दम पर क्रिकेट की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। भारत का क्रिकेट सफर संघर्षों से भरा रहा है। वर्ष 1983 का विश्व कप जीतने से पहले भारतीय टीम को एक कमजोर टीम माना जाता था। मगर कपिल देव की कप्तानी में टीम ने दुनिया को गलत साबित कर दिया। वर्ष 2007 में टी-20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप जीतना भी संघर्ष की कहानी कहता है। खिलाड़ियों ने विपरीत परिस्थितियों, मानसिक दबाव और आलोचनाओं का सामना कर अपने प्रदर्शन से जवाब दिया। चोटों के बावजूद खेलना पड़ता है। मानसिक रूप से मजबूत रहना होता है।

- समरज चौहान, कार्बी आंगलांग, असम

नशे का कारोबार

पंजाब के कई शहरों में नशीले पदार्थों का कारोबार चल रहा है। तस्करों में पुलिस-प्रशासन का कोई डर नहीं है। युवाओं की नसों में जहर घोलने वाले तस्कर हर दिन फलफूल रहे हैं। युवाओं की रग-रग में नशे का जहर घोलने वाले तस्कर पंजाब के युवाओं के लिए गड्ढे खोदने जैसा काम कर रहे हैं। ये युवाओं का जीवन बर्बाद करने पर तुले हैं। सरकार इस काले कारोबार पर अंकुश नहीं लगा सकी है। पुलिस ने 130 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। पंजाब की धरती पर बढ़ रहे इस कारोबार के पीछे पड़ोसी देश है। गुजरात से वाया मुंबई और पंजाब सहित देश के हर राज्यों में नशीले पदार्थ भेजे जाते हैं। पुलिस ने तस्करों से करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। सरकार को अब सख्त कदम उठाते हुए नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे भेजना होगा। नशे का धंधा करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे युवाओं को नशे से छुटकारा मिल सके।

- कालिलाल मांडोत, लखनऊ

शौक और जोखिम

सोशल मीडिया पर एक बहुत सारे लोग रील बना कर वीडियो और फोटो साझा कर रहे हैं। दूसरी ओर, कई युवा रील बनाने के लिए वाहनों को तेज रफ्तार में चला कर स्टंट करते हैं। इससे उनकी जान जोखिम में तो होती ही है, दूसरे लोगों की जान को भी खतरा पैदा हो जाता है। साइबर अपराधी फोटो और वीडियो का दुरुपयोग कर रहे हैं। शादी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। इसके लिए अनजान वीडियो काल पर बात न करें। ब्लैकमेल का शिकार होने पर पुलिस की मदद लें। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत फोटो साझा न करें। यह जान लें कि रील की राह में बड़े धोखे हैं। रील का नशा अधिक खतरनाक है। रील के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें।

- राजेंद्र कुमावत, जयपुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com